EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims Mains Essay

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 06 January 2026

सियाचिन के नायक कहे जाते हैं नायब सूबेदार बाना सिंह

बाना सिंह का जन्म 1949 में आज ही जम्मू-कश्मीर के कडियाल गांव में हुआ था। 1969 में जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1987 में आपरेशन राजीव के दौरान उन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कायद चौकी (अब बाना पोस्ट) को पाकिस्तानी सेना से अपने कब्जे में लेने का काम सौंपा गया। 21,153 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह चौकी दुर्गम चढ़ाई और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण लगभग अभेद्य थी। अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए, बाना सिंह ने अपनी टीम का नेतृत्व किया और चौकी पर पुन: अधिकार प्राप्त कर लिया।

Dainik Jagaran Page No-14

सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ को जनता के सामने प्रस्तुत किया

1838 में आज ही अमेरिका में सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ को जनता के सामने पेश किया था। उन्होंने तीन किमी की दूरी पर संदेश प्रसारित किया था। यह विद्युत तरंगों और मोर्स कोड के माध्यम से संदेश भेजने का एक क्रांतिकारी तरीका था। इस घटना ने लंबी दूरी के इलेक्ट्रानिक संचार की शुरुआत की।

Dainik Jagaran Page No-14

अल्फ्रेड वेगेनर ने महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया

1912 में आज ही जर्मन विज्ञानी अल्फ्रेड वेगेनर ने सबसे पहले महाद्वीपीय बहाव का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार सभी महाद्वीप कभी एक विशाल महाद्वीप 'पैंजिया' का हिस्सा थे और लाखों वर्षों में टूटकर अलग-अलग हो गए। उनके कार्य ने प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत की नींव रखी।

तेजी से बढ़ती जनसंख्या विकास की गति को बाधित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के माध्यम से ही हम सीमित संसाधनों के बीच बेहतर जीवन स्तर और मजबूत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं।

पं. जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा

बुनियादी ढांचे पर 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश

पटना, 5 जनवरी (भाषा)।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि बिहार में इस समय राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति (पीएमजी) पोर्टल पर राज्य में कुल 170 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, जिनमें कुल 7.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे चौधरी ने कहा कि ये परियोजनाएं सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, बिजली, तेल एवं गैस, दूरसंचार, शहरी अवसंरचना, स्वास्थ्य तथा अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो क्षेत्रीय संपर्क और सामाजिक-आर्थिक विकास में बिहार की बढ़ती भूमिका को दर्शाती हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा रही है।

> *चौधरी* ने कहा कि ये परियोजनाएं सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, बिजली, तेल एवं गैस, दूरसंचार, शहरी अवसंरचना, स्वास्थ्य तथा अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं।

भूमि अधिग्रहण, वैधानिक स्वीकृतियों, कानून-व्यवस्था प्रबंधन तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और परियोजना एजंसियों के साथ समन्वय के जरिए समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं से जुड़ी लगभग 96 फीसद समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। चौधरी ने कहा कि कुल 170 परियोजनाओं में से 60 परियोजनाएं पूरी होकर चालू हो चुकी हैं। इनमें 1,28,095 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।

वहीं 110 परियोजनाएं, जिनमें 5,30,094 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, वर्तमान में निर्माण अथवा कार्यान्वयन के चरण में हैं। इस प्रकार लगभग 65 फीसद परियोजनाएं निष्पादन चरण में हैं, जो राज्य में निरंतर अवसंरचना विस्तार को दर्शाता है।

Jansatta Page No-10

बिहार का केंद्र के पास 3350 करोड़ रुपये से अधिक बकाया

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : केंद्र सरकार ने योजना के नाम में तो बदलाव कर दिया, लेकिन मनरेगा के सामग्री मद में बिहार के बकाया भुगतान को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। बिहार का केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का जहां चालू वित्तीय वर्ष का छह सौ करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 का 620 करोड़ एवं जबकि 2024-25 का 2100 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। बिहार सरकार के अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान अटके होने के कारण ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और पंचायत स्तर पर कामकाज की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

- मनरेगा के मद में चालू वित्तीय वर्ष का छह सौ करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान है लंबित
- वित्तीय वर्ष 2023-24 का 620 करोड़ एवं 2024-25 का बकाया है 2100 करोड़

विदित हो कि मनरेगा में दो प्रमुख मद हैं - मजदूरी और सामग्री। मजदूरी मद का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में होता है, जबकि सामग्री मद में सड़क, नाला, तालाब, मिट्टी भराई, पुल-पुलिया, भवन मरम्मत जैसी स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण पर खर्च किया जाता है। बिहार सरकार का दावा है कि मजदूरी मद का भुगतान

अपेक्षाकृत समय पर हो जाता है, किंतु सामग्री मद की राशि केंद्र से समय पर नहीं मिलने के कारण राज्य को ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और पंचायतों को भुगतान में कठिनाई हो रही है।

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष दर वित्तीय वर्ष सामग्री मद का बकाया बढ़ता गया है। वर्तमान में यह राशि 3300 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि इस बकाया के चलते कई जिलों में कार्य एजेंसियां नए काम लेने से कतरा रही हैं, वहीं पहले से कराए गए कार्यों के भुगतान में देरी से स्थानीय स्तर पर असंतोष भी बढ़ रहा है। पंचायती राज प्रतिनिधियों का कहना है कि सामग्री मद का भुगतान नहीं होने से योजनाओं की गुणवत्ता और निरंतरता, दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। कई पंचायतों में कार्य अधूरे पड़े हैं, क्योंकि सामग्री आपूर्ति के लिए भुगतान की गारंटी नहीं मिल पा रही है। इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण का उद्देश्य भी कमजोर पड़ रहा है। विदित हो कि इस मुद्दे को लेकर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कई बार ध्यान आकृष्ट किया है। संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों से पत्राचार कर बकाया राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

बिहार का तर्क है कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और इसमें राज्यों की भूमिका केवल क्रियान्वयन की है, जबकि वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना केंद्र की जिम्मेदारी है। वहीं, जानकारों का मानना है कि यदि सामग्री मद का भुगतान समय पर होता रहे तो बिहार में जल संरक्षण, खेत-तालाब और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को नई गति मिल सकती है। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि पलायन पर भी अंकुश लगेगा।

Dainik Jagaran Page -2

अब सरकारी अनुदान पर करें मखाना की खेती

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : कृषि विभाग नए किसानों को सरकारी अनुदान पर मखाना की खेती करने का मौका दे रहा है। अनुदान पाने के लिए किसानों को 15 जनवरी तक बिहार कृषि एप या उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन करना होगा। मखाना का क्षेत्र विस्तार (खेत प्रणाली) के लिए विभागीय पोर्टल डीबीटी पर पंजीकृत किसान आवेदन कर सकते हैं। मखाना की खेती के लिए निर्धारित इकाई लागत 0.97 लाख रुपये/हेक्टेयर है, जिसमें बीज सहित अन्य इनपुट तथा हार्वेस्टिंग तक की राशि सम्मिलित है।

योजना के तहत पहले वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान राशि 36 हजार 375 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाएगी। जिसमें बीज की

16 जिलों के लिए सरकार लाई है मखाना विकास की योजना, नए मखाना किसानों को दी जाएगी प्राथमिकता, आवेदन 15 तक

राशि संबंधित आपूर्तिकर्ता को बीज प्राप्त करने के बाद और शेष राशि किसानों को पौधरोपण के बाद दी जाएगी। वहीं, एक किसान को न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) और अधिकतम पांच एकड़ (दो हेक्टेयर) में खेती पर यह लाभ मिलेगा। वहीं, मखाना बीज उत्पादन के तहत मखाना के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थानों द्वारा अनुदान पर मखाना के उन्नत प्रभेद स्वर्ण वैदेही एवं सबौर मखाना-1 के बीज का उत्पादन कराया जाएगा। मखाना बीज वितरण योजना के तहत वितरित अनुशंसित प्रभेद का बीज के मूल्य की राशि अधिकतम 225.00 रुपये प्रति किलोग्राम अनुदान के रूप में दी जाएगी।

इन जिलों के लिए है योजना

राज्य के 16 जिलों यथा कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के किसानों को इस योजना का लाभ दिया मिलेगा।

सूर्य के प्रकाश से खोजी गई मेथनाल ईंधन बनाने की तकनीक

गुवाहाटी, आइएनएस : अब भारत ईंधन से प्रदूषण नहीं फैलाएगा, बल्कि सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक कार्बन डाइआक्साइड से ही सूर्य प्रकाश की मदद से मेथनाल ईंधन बनाएगा। आइआइटी गुवाहाटी ने सूर्य प्रकाश की मदद से मेथनाल बनाने की तकनीक खोज ली है। यह स्वच्छ ईंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने फोटोकैटेलिटिक मेटेरियल (उत्प्रेरक) विकसित किया है, जो सूरज की रोशनी का उपयोग करके कार्बन डाइआक्साइड को मेथनाल में बदल सकता है। इससे पेट्रोलियम आधारित ईंधनों पर निर्भरता कम होगी जो कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन का स्रोत है। इससे पर्यावरण को और नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा, वहीं पेट्रोलियम पदार्थों के आयात कम होने से विदेशी मुद्रा भी बचेगी।

- सूरज की रोशनी का उपयोग कर कार्बन डाइआक्साइड को मेथनाल में बदलने वाला फोटोकैटेलिटिक मैटेरियल विकसित
- स्वच्छ ईंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि, कम होगी पेट्रोलियम ईंधनों पर निर्भरता

आईआईटी गुवाहाटी। फाइल

यह अध्ययन जर्नल आफ मटेरियल्स साइंस में प्रकाशित हुआ है। थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट निर्माण इकाइयों, स्टील उत्पादन केंद्रों और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों जैसे उद्योगों में इस नई तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा।

आइआइटी गुवाहाटी के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की प्रोफेसर महुया डे ने बताया कि पेट्रोलियम आधारित ईंधनों पर निर्भरता कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जन का बड़ा कारण है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइआक्साइड को हरित ईंधन में बदलना इस दिशा में आशाजनक तकनीक है। इससे पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दुनियाभर के शोधकर्ता इस चुनौती का समाधान करने के लिए पहले से ही ग्रेफाइटिक कार्बन नाइट्राइड का उपयोग कर रहे हैं, जो कम लागत वाला गैर-जहरीला पदार्थ है। हालांकि, तीव्र ऊर्जा हानि और कम ईंधन उत्पादन के कारण अब तक कोई समाधान विकसित नहीं हो सका।

आइआइटी गुवाहाटी की टीम ने इस चुनौती का समाधान निकालते हुए ग्रेफाइटिक कार्बन नाइट्राइड को फ्यू-लेयर ग्रेफीन के साथ मिलाया। ग्रेफीन बेहतर विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है। यह अल्ट्रा-पतला कार्बन मेटेरियल उत्प्रेरक के भीतर ऊर्जा हानि कम करने में मदद करता है।

शोध में यह भी पाया गया कि ग्रेफीन की मौजूदगी से कैटेलिस्ट लंबे समय तक सक्रिय रहता है, जिससे सूरज की रोशनी का बेहतर अवशोषण होता है। परीक्षण किए गए विभिन्न संयोजनों में 15 प्रतिशत ग्रेफीन वाला कैटेलिस्ट सबसे अधिक प्रभावी साबित हुआ। इसमें अच्छी स्थिरता भी पाई गई, जो व्यावहारिक उपयोग के लिए आवश्यक है। अगला कदम इस तकनीक को व्यावहारिक स्तर पर लागू करना है। आगे का कदम इस तकनीक को व्यावहारिक स्तर पर लागू करना है। टीम एक दीर्घकालिक फोटोकेटालिटिक प्रणाली विकसित करने की योजना भी बना रही है, जो औद्योगिक कार्बन डाइआक्साइड को स्वच्छ ईंधनों में बदल सके। इस प्रकार, आइआइटी गुवाहाटी की यह खोज न केवल ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Dainik Jagaran Page -14

इसरो के उपकरण ने पृथ्वी पर बरसते धूल कणों का पता लगाया

बेंगलुरु, प्रेट : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पहले स्वदेशी धूल डिटेक्टर उपकरण द डस्ट एक्सपेरिमेंट (डीईएक्स) ने पृथ्वी पर बरसते अंतरग्रहीय धूल कणों (आइडीपी) का पता लगाया है। डीईएक्स को एक जनवरी को लांच किया गया था।

ये धूल कण धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों के मलबे हैं और अंतरिक्षयानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसरो ने सोमवार को बताया कि आइडीपी पृथ्वी से हर हजार सेकेंड में टकराते हैं। इसरो के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा विकसित डीईएक्स उच्च गति के आइडीपी की खोज के लिए तैयार किया गया है।

140 डिग्री चौड़े डिटेक्टर ने कक्षीय मलबे (धूल) के प्रभावों के संकेतों को सफलतापूर्वक रिकार्ड किया। डीईएक्स तीन किलोग्राम का धूल डिटेक्टर है। इसे केवल 4.5 वाट पावर खपत के साथ

- पहला स्वदेशी धूल डिटेक्टर उपकरण है द डस्ट एक्सपेरिमेंट

उच्च गति के अंतरिक्ष धूल प्रभावों को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो ने कहा, इस समय हमारे पास शुक्र के घने वायुमंडल या मंगल के पतले वायुमंडल में ब्रह्मांडीय धूल के माप नहीं हैं। डीईएक्स डिटेक्टर का ब्लूप्रिंट है जो किसी भी ग्रह पर ब्रह्मांडीय धूल कणों का अध्ययन कर सकता है भले ही उसका वायुमंडल हो या न हो। आइडीपी को मापने की क्षमता अंतरिक्ष वातावरण की निगरानी के लिए आवश्यक है। यह चंद्रमा, मंगल और भविष्य के मानव मिशनों की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसरो के इस प्रयास से अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई दिशा मिल सकती है, जो भविष्य में मानवता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

Dainik Jagaran Page -14

व्यक्तित्व

काम्या : महज 18 साल की उम्र में दक्षिणी ध्रुव का साहसिक अभियान

जनसत्ता संवाद

भारत की 18 वर्षीय युवती काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रच दिया है। वे दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। काम्या ने 27 दिसंबर 2025 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर यह साहसिक उपलब्धि हासिल की। इस अभियान के दौरान उन्होंने लगभग 115 किलोमीटर की दूरी स्की और ट्रेकिंग के माध्यम से तय की। अंटार्कटिका की कठोर परिस्थितियों- माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, तेज बर्फीली हवाएं और 'वाइटआउट' जैसी स्थितियों - में काम्या ने पूरी यात्रा पैदल और अपने साजो-सामान से भरी स्लेज को खींचते हुए पूरी की। यह अद्वितीय साहसिक अभियान उनके मानसिक संकल्प और दृढ़ता का प्रमाण है।

काम्या भारतीय नौसेना के अधिकारी कमांडर एस कार्तिकेयन और शिक्षिका लावण्या कार्तिकेयन की पुत्री हैं। उन्होंने नेवी चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ाई की है, जहां से उन्हें अनुशासन और साहसिक गतिविधियों की प्रेरणा बचपन से ही मिली। उनके दक्षिणी ध्रुव तक के इस असाधारण प्रयास पर भारतीय नौसेना ने उन्हें सार्वजनिक रूप से बधाई दी है। काम्या ने 18 वर्ष की आयु से पहले ही पर्वतारोहण की दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2024 में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेवन समिट्स चैलेंज पूरा किया, जिसके अंतर्गत सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई शामिल है। ये हैं - माउंट एवरेस्ट (एशिया), अकोंकागुआ (दक्षिण अमेरिका), डेनाली (उत्तरी अमेरिका), किलीमंजारो (अफ्रीका), एल्ब्रुस (यूरोप), विंसन (अंटार्कटिका), कोजिअस्को (आस्ट्रेलिया)। काम्या माउंट एवरेस्ट पर नेपाल पक्ष से चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे युवा महिला भी बनीं। इससे पहले उन्होंने 2020 में अकोंकागुआ और 2018 में एल्ब्रुस पर भी सफल चढ़ाई की थी, एल्ब्रुस से स्की-डिसेंट कर पाना उनके उम्र में एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है। काम्या अब एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम की अंतिम चुनौती के करीब हैं - उत्तरी ध्रुव तक स्की करना। उन्होंने सेवन समिट्स और दक्षिणी ध्रुव दोनों फतह कर लिए हैं। यदि वे उत्तरी ध्रुव तक सफलतापूर्वक स्की करती हैं, तो वह इस वैश्विक कीर्तिमान को पूरा करने वाली सबसे युवा भारतीय बन सकती हैं। काम्या की यह यात्रा न केवल साहस का प्रतीक है, बल्कि यह भारत के युवा वर्ग में रोमांच, अनुसंधान और धैर्य के नए आयाम खोलती है।

कौन हैं गिग वर्कर्स

ऑनलाइन ऐप से आपने खाना या राशन आर्डर किया और 10 मिनट के अंदर मंगाये गये सामान के साथ एक आदमी आपके दरवाजे की घंटी बजायेगा, वही है गिग वर्कर, जिसे मंथली सैलरी नहीं, बल्कि राइड या डिलीवरी के आधार पर पेमेंट मिलता है. गिग वर्क में, जिसे गैर-मानक कार्य भी कहा जाता है, पारंपरिक, दीर्घकालिक, प्रत्यक्ष-नियुक्त रोजगार के बाहर आय सृजित करनेवाली गतिविधियां शामिल होती हैं.

- भारत के 500 से अधिक शहरों में स्विगी, जोमैटो, ओला और उबर जैसी कंपनियां सक्रिय हैं, जहां लाखों गिग वर्कर काम करते हैं.
- दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद जैसे महानगर आज गिग इकोनॉमी का सबसे बड़ा केंद्र हैं.
- वर्तमान में भारत के कुल कार्यबल का 2 फीसदी से अधिक हिस्सा गिग इकोनॉमी से जुड़ा है.
- भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 2020–21 के 77 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1.2 करोड़ दर्ज की गयी है.
- इस क्षेत्र में बीते वर्षों में 17 फीसदी की सालाना वृद्धि देखी गयी है, जबकि पिछले एक साल (2024-25) में ही इसमें 38 फीसदी का भारी उछाल आया है.

नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गिग वर्कर्स किस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं -

47% गिग वर्कर मीडियम स्किल्ड कार्यों में हैं.

31% लो स्किल्ड काम में हैं.

22% हाई स्किल्ड जॉब में हैं.

- गिग और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, इ-श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार.
- सबसे ज्यादा गिग वर्कर रिटेल व्यापार और बिक्री (लगभग 27 लाख) और परिवहन क्षेत्र (लगभग 13 लाख) में सक्रिय हैं.

कारण जिन्होंने बनाया गिग वर्किंग को लोकप्रिय

55% लोग नौकरी के साथ अतिरिक्त कमाई के लिए गिग वर्किंग करते हैं.

48% ने परिवार को समय देने और काम को मैनेज करने के लिए चुना है यह काम

22% ने कमाई का कोई जरिया न होने पर गिग वर्कर बनने का विकल्प चुना

19% एक अच्छी स्थायी नौकरी ढूंढने तक गुजारा करने के लिए इस काम को कर रहे हैं.

झारखंड व बिहार समेत कई राज्य बना चुके हैं गिग वर्कर्स के लिए एक्ट

- बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों (झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक के बाद) में शामिल हो गया है, जिसने गिग वर्कर्स के लिए अलग से कानून बनाया है. जुलाई 2025 में बिहार विधानसभा ने 'बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अधिनियम, 2025' पारित किया-
- इस अधिनियम के तहत गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया गया है.
- दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ और मातृत्व अवकाश (90 दिन) जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान है.
- ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को 4 लाख रुपये तक की सहायता राशि और अस्पताल में भर्ती होने पर सहायता का प्रावधान है.
- हर गिग वर्कर को एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जायेगा ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें.

सेक्टर एवं गिग वर्कफोर्स शेयर (2025-26)

भारतीय गिग वर्कर्स की सबसे अधिक भागीदारी लॉजिस्टिक्स व सर्विस सेक्टर में है.

सेक्टर	गिग वर्कर	मुख्य गतिविधियां
रिटेल और इ-कॉमर्स	35 से 40 प्रतिशत	डिलीवरी पार्टनर, वेयरहाउस स्टाफ, पैकेजिंग
परिवहन	20 से 25 प्रतिशत	कैब ड्राइवर्स, बाइक टैक्सी (ओला, ऊबर आदि)
आइटी और सॉफ्टवेयर	15 से 20 प्रतिशत	कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एंट्री, एआइ ट्रेनिंग
घरेलू एवं व्यक्तिगत सेवाएं	10 से 15 प्रतिशत	अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म - ब्यूटी, रिपेयर आदि
शिक्षा	5 से 8 प्रतिशत	ऑनलाइन ट्यूटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आदि

Dainik Jagaran Page -3

सिंधु नदी जल संधि का निलंबन जारी रहेगा : मनोहर लाल

संवाद सहयोगी, जागरण ● किश्तवाड़ : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को कहा कि सिंधु जल संधि का निलंबन जारी रहेगा। भारत सरकार अपने निर्णय पर अडिग है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए हमारी नदियों के एक-एक बूंद पानी पर हमारा हक है।

केंद्रीय मंत्री अपने दो दिवसीय दौरे पर जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में हैं। सोमवार को दूसरे दिन उन्होंने पकल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद किरू और क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में पहुंचकर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने एनएचपीसी और परियोजनाओं में कार्यरत अन्य कंपनियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से बातचीत कर परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बता दें कि निर्माणाधीन पकल डूल परियोजना 850 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट और क्वार परियोजना 540 मेगावाट की है और ये चिनाब नदी पर हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ पानी के बंटवारे को लेकर सिंधु जल संधि तोड़ दी थी।

- कहा, हमारी नदियों के एक-एक बूंद पानी पर भारत का हक
- पकल डूल, किरू व क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निरीक्षण

किश्तवाड़ दौरे के दौरान अधिकारियों से मिलते केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। जागरण

Hindustan Page

उपलब्धि | आधुनिक तकनीक समुद्री चुनौतियों से निपटने का माध्यम, इसी के जरिए समस्याओं का होगा समाधान होगा, तटरक्षक बलों ने दुश्मनों को भी अपनी ताकत से चेताया

राजनाथ ने पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत राष्ट्र को समर्पित किया

पणजी, एजेंसी। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के बेड़े में सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रताप' शामिल हो गया है। सोमवार को इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तट रक्षक बल ने दुश्मन के मन में ये डर बैठा दिया है कि अगर उसने भारत की समुद्री सीमा की ओर देखा तो वे उसे देखने लायक नहीं छोड़ेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आधुनिक तकनीक समुद्री चुनौतियों से निपटने का माध्यम है। इसी के जरिए समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि तटरक्षक बलों ने दुश्मनों को भी अपनी ताकत से चेताया है। बल ने दुश्मन को स्पष्ट बता दिया है कि अगर उसने आंख उठा कर भारत की समुद्री सीमा की ओर देखा तो भारतीय तटरक्षक बल उसे देखने लायक नहीं छोड़ेगा। बल के इसी विश्वास का नतीजा है कि भारत के तटीय इलाकों से दुश्मन अब कोई दुस्साहस की कोशिश भी नहीं करता। उन्होंने कहा कि पोत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत 'समुद्र प्रताप' को बल में शामिल किया। यह अब तक तटरक्षक बल का सबसे बड़ा जहाज है।

दावोस जाएंगे 10 राज्यों के प्रतिनिधि

डब्ल्यूईएफ सम्मेलन में जाएगा बड़ा प्रतिनिधिमंडल, अगुआई करेंगे शिवराज सिंह और अश्विनी वैष्णव

बीएस संवाददाता

केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और अश्विनी वैष्णव की अगुआई में देश के 10 राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधि इस महीने के अंत में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चौहान और वैष्णव के अलावा दो अन्य केंद्रीय मंत्री और पांच मुख्यमंत्री एवं दो उप-मुख्यमंत्री दावोस जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहेंगे। निजी क्षेत्र की कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दर्जनों शीर्ष व्यापारिक प्रतिनिधि भी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे।

आगामी 19 से 23 जनवरी तक होने वाली डब्ल्यूईएफ की सालाना बैठक में विशाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में जा रहा है जब देश ने निर्यात में विविधता लाने और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज के प्रयास तेज कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री चौहान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री वैष्णव के अलावा डब्ल्यूईएफ सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य केंद्रीय मंत्रियों में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू शामिल हैं।

डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले मुख्यमंत्रियों में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, असम के हिमंत विश्व शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं। कर्नाटक और गुजरात के उप-मुख्यमंत्री क्रमशः डी के शिवकुमार और हर्ष संघवी भी वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात और निवेश संवर्धन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' भी शामिल हो सकते हैं। झारखंड और केरल के प्रतिनिधिमंडल भी स्विट्जरलैंड जाएंगे।

शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय मंत्री

अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री

इन राज्यों में आंध्र प्रदेश (2025 में डब्ल्यूईएफ सम्मेलन में भाग लिया था) का एक अलग मंडप होगा। राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश दक्षिणी राज्य के निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और अपने उत्पादों (खासकर झींगा मछली) के लिए निर्यात बाजारों की तलाश करेंगे। अमेरिकी शुल्कों के कारण भारत से निर्यात प्रभावित हुआ है।

इस महीने की शुरुआत में असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस पूर्वोत्तर राज्य को पिछले पांच वर्षों के दौरान 45 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि असम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में 4,10,724 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 7,41,626 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। शर्मा ने कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे औद्योगिक रूप से उन्नत राज्यों के साथ दावोस में डब्ल्यूईएफ की सालाना बैठक में प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर असम की आर्थिक वृद्धि को सम्मान दिया है। शर्मा ने 1 जनवरी को गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'इससे हमें प्रमुख उद्योगपतियों के साथ असम के बारे में बात करने का अवसर मिलेगा।'

इस वर्ष के डब्ल्यूईएफ सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।

दावोस में वार्षिक समागम में भाग लेने वाले संभावित भारतीय व्यापारिक नेताओं में टाटा समूह के एन चंद्रशेखरन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, बजाज समूह के संजीव बजाज, गोदरेज इंडस्ट्रीज के नादिर गोदरेज, जेएसडब्ल्यू समूह के सज्जन और पार्थ जिंदल, भारत फोर्ज, वेदांत और अपोलो के शीर्ष नेता, जीरोधा के निखिल कामत, भारती समूह के सुनील भारती मित्तल, इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी, विप्रो के ऋषद प्रेमजी, एस्सार के सीईओ प्रशांत रुइया और रीन्यू के सीईओ सुमंत सिन्हा शामिल हैं। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष अरविंदर सिंह सहने, गेल के संदीप कुमार गुप्ता, भारतीय स्टेट बैंक के चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, एनटीपीसी के गुरदीप सिंह और आरईसी लिमिटेड के जितेंद्र श्रीवास्तव सहित कई पीएसयू प्रमुख भी भाग लेंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन इरानी कुछ साल पहले दावोस में ही स्थापित एलायंस फॉर ग्लोबल गुडः जेंडर इक्विटी ऐंड इक्वलिटी की संस्थापक एवं चेयरपर्सन के रूप में भाग लेने वाली हैं।

इस वर्ष डब्ल्यूईएफ की सालाना बैठक का विषय 'संवाद की भावना' है। डब्ल्यूईएफ ने कहा है कि यह बैठक एक निष्पक्ष मंच का लाभ उठाने का प्रयास करेगी। दुनिया में साझा चुनौतियों का सामना करने और भविष्य को परिभाषित करने वाले नवाचारों को चलाने के लिए डब्ल्यूईएफ वैश्विक नेताओं एवं कारोबारी दिग्गजों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाता है।

शिखर सम्मेलन पांच वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसमें सार्वजनिक-निजी सहयोग काफी मदद कर सकता है। इनमें दुनिया में जारी उठापटक के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना, आर्थिक वृद्धि के नए स्रोत तैयार करना, लोगों में बेहतर निवेश, बड़े पैमाने पर जिम्मेदारी के साथ नवाचार का इस्तेमाल करना और संपन्नता को बढ़ावा देना है।

Business Standard Page -10

ट्रंप के निशाने पर क्यों हैं ये देश

अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद से, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों ने कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको, ईरान और डेनमार्क के एक स्वशासी क्षेत्र ग्रीनलैंड सहित कई अन्य देशों और क्षेत्रों को कब्जा करने या हमले की चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं ये देश ट्रंप के निशाने पर क्यों हैं...

अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा है ग्रीनलैंड

आर्कटिक क्षेत्र में स्थित ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, में अमेरिका का लंबे समय से सुरक्षा हित रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर आक्रमण किया और वहां सैन्य और रेडियो स्टेशन स्थापित किए। युद्ध के बाद भी अमेरिकी सेना ग्रीनलैंड में बनी रही। पिटुफिक अंतरिक्ष अड्डा, जिसे पहले थुले हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था, तब से अमेरिका द्वारा संचालित किया जा रहा है। यदि रूस अमेरिका की ओर मिसाइलें भेजता है, तो परमाणु हथियारों के लिए सबसे छोटा रास्ता उत्तरी ध्रुव और ग्रीनलैंड से होकर गुजरेगा। इसलिए पिटुफिक अंतरिक्ष अड्डा अमेरिका की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, चीन और रूस ने हाल के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए अमेरिका भी अपने प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला करने के लिए आर्कटिक में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना चाहता है। ट्रंप ग्रीनलैंड के विशाल भूभाग में खनन की संभावनाओं में भी रुचि रखते हैं।

रूस से क्यूबा की नजदीकी

1959 में फिदेल कास्त्रो के सत्ता में आने के बाद उनके सुधार अमेरिकी व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाने लगे। दोनों देशों में टकराव बढ़ा। कास्त्रो ने समर्थन के लिए अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, सोवियत संघ की ओर रुख किया। क्यूबा का सोवियत संघ के साथ गठबंधन ही वह मुख्य कारण था जिसके चलते अमेरिका क्यूबा को एक सुरक्षा खतरा मानता था।

कट्टर दुश्मन ईरान

अमेरिका और ईरान दशकों से एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। 2019 में यह शत्रुता और भी तीव्र हो गई। 2020 में पेंटागन द्वारा ईरान के सबसे शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए हवाई हमले का आदेश देने के बाद यह चरम पर पहुंच गई। दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत 20वीं सदी के पूर्वार्ध में मध्य पूर्व में अंग्रेजों के आगमन से हुई थी। यह कहानी तेल, शीत युद्ध, क्षेत्र में सत्ता के लिए संघर्ष और एक बंधक संकट से जुड़ी है।

मेक्सिको पर ट्रंप का दबाव

ट्रंप मेक्सिको से प्रवासन और मादक पदार्थों की तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने आव्रजन, व्यापार और सुरक्षा को लेकर मेक्सिको पर नए सिरे से दबाव डालना शुरू किया था।

कभी अमेरिका का भरोसेमंद सहयोगी था कोलंबिया

कोलंबिया, जो कभी लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था, अब एक राजनयिक विवाद का केंद्र बन गया है। वर्ष 2000 में प्लान कोलंबिया की शुरुआत के बाद से, अमेरिका और कोलंबिया की नीतियां मादक पदार्थों की रोकथाम, सैन्य सहयोग और राज्य निर्माण में भारी निवेश के साथ एक रहीं। हालांकि, 2010 के दशक के मध्य तक प्राथमिकताओं में अंतर के कारण अमेरिका और कोलंबिया के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। 2022 में पेट्रो के सत्ता में आने के साथ, जिन्होंने नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध समाप्त करने का वादा किया, द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए।

जागरण रिसर्च

ट्रंप की धमकी से लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक नाराजगी

कोलंबिया के राष्ट्रपति ने लैटिन अमेरिकी देशों से की एकजुट होने की अपील

ग्रीनलैंड के पीएम ने कहा- बस बहुत हुआ, ग्रीनलैंड को मिलाने का सपना न देखें

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद लैटिन अमेरिकी देशों से लेकर यूरोप तक नाराजगी है। कोलंबिया ने जहां लैटिन अमेरिकी देशों से एकजुट होने की अपील की, वहीं ग्रीनलैंड को लेकर नार्डिक व बाल्टिक देशों समेत पूरे यूरोप ने अमेरिका का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने भी वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अस्थिरता बढ़ने पर चिंता जताई।

न्यूयार्क टाइम्स के मुताबिक, ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के ट्रंप के दावे के बाद डेनमार्क व ग्रीनलैंड समेत पूरे यूरोप में तनाव बढ़ गया है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप वहां भी वेनेजुएला जैसा कुछ कर सकते हैं। ग्रीनलैंड के पीएम जेन्स फ्रेडरिक नीलसन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि बस, बहुत हुआ। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का सपना न देखें। आर्कटिक द्वीप का भविष्य यहां के लोग तय करेंगे। नार्डिक और बाल्टिक देशों ने भी डेनमार्क व ग्रीनलैंड के प्रति समर्थन दोहराया है। फ्रांस भी ग्रीनलैंड के साथ खड़ा दिख रहा है। डेनमार्क के पीएम मेट्टे फ्रेडरिकसन ने कहा, ट्रंप का ये कहना बेमतलब है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। ट्रंप धमकाना बंद कर दें। ये बात कई बार कही जा चुकी है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। जर्मनी के विदेश मंत्री जान वेडफल ने कहा, अगर ग्रीनलैंड को खतरा है तो नाटो इसकी सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा कर सकता है। यूरोपीय संघ ने कहा, हम राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत को बनाए रखने पर जोर देते हैं। ब्रिटिश पीएम कीएर स्टार्मर ने कहा, ग्रीनलैंड का भविष्य दूसरे लोग तय नहीं कर सकते हैं। इसका अधिकार डेनमार्क और ग्रीनलैंड के पास रहना चाहिए।

कोलंबिया ने एकजुटता का किया आह्वान: ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी पर कोलंबिय के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने लैटिन अमेरिकी देशों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए एक्स पर 700 शब्दों की पोस्ट में ड्रग तस्करी से लड़ने के मामले में अपनी सरकार के ट्रैक रिकार्ड का बचाव किया। उन्होंने "दुनिया के इतिहास में कोकेन की सबसे बड़ी जब्ती" अभियान का भी हवाला दिया। कहा, मैं नाजायज नहीं हूं, न ही कोई नार्को हूं। मेरे पास संपत्ति के तौर पर सिर्फ मेरा पारिवारिक घर है, जिसके लिए मैं अब भी वेतन से भुगतान करता हूं। कहा, उन्होंने मानवीय कानून का पालन करते हुए ड्रग्स से जुड़े सशस्त्र समूहों के खिलाफ बमबारी का आदेश दिया है। कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया में कहा कि एक चुने हुए नेता को ऐसी धमकी देना अस्वीकार्य है। ट्रंप का बयान देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी और अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों के खिलाफ है।

मेक्सिको सिटी के नेशनल पैलेस में सोमवार को संवाददाताओं को संबोधित करतीं राष्ट्रपति क्लाडिया शेनबाम। एएफपी

मेक्सिको में अमेरिकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाडिया शेनबाम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को खारिज करते हुए कहा कि देश के आंतरिक मामलों में अन्य देशों की दखलंदाजी को हम सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि मेक्सिको एक संप्रभु देश है और वह अमेरिका के साथ ड्रग तस्करी और सुरक्षा के मामलों में सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सहयोग के लिए हम सदा तैयार हैं, लेकिन दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेनबाम ने कहा कि ये दोहराना जरूरी है कि मेक्सिको में जनता शासन करती है। उन्होंने मीडिया से कहा कि मेक्सिको में अमेरिकी दखल की कोई संभावना नहीं है।

कई बार भारत के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं ट्रंप

प्रथम पृष्ठ से आगे

ट्रंप गत पांच-छह माह में कई बार भारत के लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर के इन्कार करने और विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान देने के बावजूद वह लगातारदावा करते रहे हैं कि मई, 2025 में पाकिस्तान पर भारत के आपरेशन सिंदूर को उन्होंने इन दोनों देशों के सथ कारोबार नहीं करने की धमकी देकर खत्म की थी।

कूटनीतिक विशेषज्ञ ने लापरवाही भरा बयान बताया : ट्रंप ने जो भारत पर और ज्यादा शुल्क लगाने की बात कही है, उस पर भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि कूटनीतिक विश्लेषक इसे लापरवाही भरा बयान बता रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा है कि यह बयान उनकी आत्ममुग्धता की गहराई को दर्शाता है। वह सोचते हैं कि दुनिया का यह कर्तव्य है कि उन्हें खुश रखे। चूंकि खुशी को मापा नहीं जा सकता और कोई भी हर समय खुश नहीं रह सकता, इसलिए किसी को नहीं पता कि उनकी खुशी की सीमा क्या है और उनका मूड कैसे बदल रहा है। वह बहुत ही लापरवाही से और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं।

किसी देश को दुनिया का न्यायाधीश वनने की नहीं दे सकते अनुमति : चीन

- कहा, हमने कभी यह नहीं माना कि कोई भी देश दुनिया की पुलिस के रूप में कार्य कर सकता है
- सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए

बीजिंग, रायटर : अमेरिका की ओर से निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि बीजिंग किसी भी देश को "विश्व का जज" बनने की अनुमति नहीं दे सकता। हालांकि उन्होंने अमेरिका का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया।

वांग ने रविवार को बीजिंग में अपने पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार से हुई बैठक के दौरान कहा, "हमने कभी यह नहीं माना कि कोई भी देश दुनिया की पुलिस के रूप में कार्य कर सकता है, न ही हम यह स्वीकार करते हैं कि कोई भी राष्ट्र दुनिया का न्यायाधीश होने का दावा कर सकता है।" "सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि बीजिंग एक कूटनीतिक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। विश्लेषकों का कहना है कि व्यापार वार्ताओं में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में बीजिंग की सफलता ने चीन के आत्मविश्वास को और मजबूत किया है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला सरकार की देखरेख करेगा, बीजिंग और काराकास के बीच 2023 में हुए "हर मौसम में कायम रहने वाली व्यापक रणनीतिक साझेदारी" के लिए एक कड़ी परीक्षा है, जो लगभग 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों का प्रतीक है। चीन ने 2017 में अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रतिबंधों को कड़ा करने के बाद से वेनेजुएला को आर्थिक सहायता प्रदान की है, और 2024 में लगभग 1.6 अरब डालर मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है। सीमा शुल्क आंकड़ों से पता चलता है कि चीन ने लगभग आधी खरीद कच्चे तेल की थी। अमेरिका हमले के बाद चीन ने कार्रवाई को गलत बताते हुए मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की थी।

Dainik jagaran Page No-11

अमेरिका से तनातनी के बीच यूरोपीय संघ से बढ़ रही भारत की निकटता

जयप्रकाश रंजन • जागरण

- उर्सुला व एंटोनियो कोस्टा होंगे गणतंत्र दिवस के राजकीय मेहमान
- फ्रेडरिक इसी माह और इमैनुअल मैक्रों अगले माह आएंगे भारत

नई दिल्ली: अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में आई तल्खी के बीच नई दिल्ली ने यूरोपीय संघ (ईयू) और इसके प्रमुख सदस्य देशों के साथ संबंधों को नई गति देने का फैसला किया है। जनवरी-फरवरी 2026 का कैलेंडर इस रणनीतिक बदलाव की गवाही दे रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर इस समय फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। 10 जनवरी तक चलने वाली उनकी यात्रा के ठीक दो दिन बाद जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आ रहे हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ के दिग्गज नेता- उर्सुला वान डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा 26 जनवरी, 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के राजकीय मेहमान होंगे। इसके दो सप्ताह बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मुंबई व नई दिल्ली की यात्रा पर आएंगे। इन तीनों अवसरों पर भारत का यूरोपीय संघ के देशों के साथ कारोबारी संबंधों के साथ ही सुरक्षा, रक्षा व ऊर्जा के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर बात होगी। कूटनीतिक जानकार इसे हाल के वर्षों में भारत की तरफ से दुनिया की कई शक्तियों के साथ अलग-अलग तालमेल बनाने की कोशिश को और गति देने के तौर पर देख रहे हैं।

जानकारों के मुताबिक, 12 जनवरी को जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज दो दिवसीय यात्रा पर भारत आने वाले हैं। सत्ता संभालने के बाद यह उनकी एशिया के किसी देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रक्षा सहयोग, पनडुब्बी सौदे, व्यापार और हिंद-प्रशांत रणनीति जैसे मुद्दे इस यात्रा का मुख्य एजेंडा होगा।

Dainik jagaran Page No-14

सम-सामयिक

काराकस : अमेरिका के सैन्य अभियान की वैधता पर सवाल

जनसत्ता संवाद

अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ ले जाने के अभियान की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के लिए आपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजाल्व' का घोषित उद्देश्य उस व्यक्ति को पकड़ कर ले जाना था, जिसके बारे में उसका दावा था कि उसने 2024 के चुनावों में धांधली कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति का पद हासिल किया था। महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि न्यूयार्क की एक संघीय अदालत ने उस पर अमेरिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी का सिंडिकेट चलाने और आतंकवाद से जुड़े होने का अभियोग लगाया था।

अदालत के अभियोग पत्र में कहा गया है, 'पिछले 25 वर्षों से वेनेजुएला के नेताओं ने सार्वजनिक विश्वास के पदों का दुरुपयोग किया है और अमेरिका में बड़ी मात्रा में कोकीन बेची है। आरोपी निकोलस मादुरो मोरोस इस भ्रष्टाचार में सबसे आगे है।' हालांकि, अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की जा रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए पर्याप्त थे।

चैथम हाउस थिंक टैंक में प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय कानून कार्यक्रम के निदेशक मार्क वेल्लर ने सैन्य अभियान को 'वेनेजुएला की संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट रूप से उल्लंघन' बताया है। संरा चार्टर के अनुच्छेद 2 (4) में कहा गया है कि 'सभी सदस्य अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल के प्रयोग या धमकी से परहेज करेंगे।' इसका अपवाद अनुच्छेद 51 है, जो 'संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य पर सशस्त्र हमले की स्थिति में व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार' को मान्यता देता है।

कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी का हवाला देते हुए अमेरिकी सरकार 'सशस्त्र हमले' को जायज नहीं ठहरा सकती। वेल्लर ने लिखा है, 'अंतरराष्ट्रीय कानून में, केवल सैन्य या इसी तरह के साधनों से किया गया प्रत्यक्ष हमला ही आत्मरक्षा का आधार माना जाता है।' संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी कहा कि वे वेनेजुएला में हिंसा से बेहद चिंतित हैं और ये घटनाक्रम खतरनाक मिसाल कायम करते हैं।

वेनेजुएला अभियान को लेकर तर्क दिया जा रहा है कि इससे चीन जैसे देशों को ताइवान समेत कई अन्य देशों में बिना किसी ठोस औचित्य के अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू करने का प्रोत्साहन मिल सकता है। न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा कि वेनेजुएला ओपिओइड फेंटानिल का 'महत्त्वपूर्ण उत्पादक' नहीं है। बल्कि, यह कार्रवाई दिसंबर 2025 में जारी की गई नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत किए गए पुनर्गठन का हिस्सा है, जिसमें 'पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व को बहाल करने' की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

मादुरो के मामले से मिलता-जुलता एक मामला 1989 में पनामा के तत्कालीन नेता जनरल मैनुअल नोरीगा की अमेरिका द्वारा गिरफ्तारी का था। हालांकि वे पहले अमेरिका के सहयोगी थे, लेकिन उनकी वफादारी पर संदेह पैदा हुआ और अमेरिका ने उन पर मादक पदार्थों से संबंधित आरोप लगाकर जवाब दिया। इस मामले में अमेरिकी सेना भी देश में दाखिल हुई थी।

निकारागुआ का मामला

निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (1984) मामले में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) मध्य अमेरिकी देश के खिलाफ अमेरिकी सैन्य बल के प्रयोग के मामले पर विचार कर रहा था। अन्य बातों के अलावा, अमेरिका शीत युद्ध के उद्देश्यों और साम्यवाद को रोकने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे दक्षिणपंथी समूहों की गतिविधियों का समर्थन कर रहा था।

Jansatta Page No-7

टैरिफ फिर बढ़ा तो रुपये और निर्यात पर दिखेगा असर

अमेरिका ने पिछले साल भारतीय आयात पर लगाया था 50 प्रतिशत टैरिफ, गारमेंट और लेदर जैसे क्षेत्र हुए थे प्रभावित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक और भविष्य में भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर और टैरिफ लगाने की धमकी अगर सच साबित होती है तो शेयर बाजार, डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में और गिरावट दिखाई देगी। इतना ही नहीं रोजगारपरक सेक्टर के अमेरिका को होने वाला निर्यात भी प्रभावित हो सकता है।

पिछले साल अगस्त से अमेरिका में भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर 50 प्रतिशत शुल्क लागू है। उसके बाद से अमेरिकी बाजार में गारमेंट, लेदर आइटम, जेम्स व ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात की वृद्धि दर घटी है। पिछले साल मई-जून की तुलना में सितंबर और अक्टूबर में अमेरिका को होने वाले निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। मोबाइल, फार्मा जैसे कुछ उत्पादों को ट्रंप सरकार ने शुल्क से मुक्त रखा है, इसलिए इनके निर्यात में बढ़ोतरी से कुल निर्यात को समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात में अब भी वृद्धि दिख रही है।

- पिछले साल मई-जून की तुलना में सितंबर-अक्टूबर में अमेरिका को होने वाले निर्यात में आई गिरावट
- पिछले साल ब्रिटेन, ओमान व न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया
- फिर से अमेरिकी टैरिफ बढ़ने पर भारत को उसकी भरपाई के लिए नए बाजार तलाशने होंगे

एफआइआइ की भारी मात्रा में बिकवाली

अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद ही डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में ह्रास होना शुरू हुआ और एक डालर का मूल्य 90 रुपये के पार चला गया। सरकार के अधिकारियों से लेकर बाजार विशेषज्ञ तक कई बार यह बयान दे चुके हैं कि भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बाद रुपये में मजबूती आएगी। ट्रंप की नई धमकी से रुपये में और कमजोरी आ सकती है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप के नए बयान के बाद विदेशी संस्थागत निवेश (एफआइआइ) भी भारतीय बाजार से निकलेंगे, जिससे शेयर बाजार प्रभावित हो सकता है। पिछले साल अगस्त के बाद से भारतीय बाजार से भारी मात्रा में एफआइआइ की निकासी हुई।वर्ष 2025 में तीन लाख करोड़ एफआइआइ की बिकवाली की गई।

शुल्क बढ़ने पर अमेरिकी आर्डर में आएगी और कमी

गारमेंट और जेम्स व जेलरी के निर्यातकों ने बताया कि टैरिफ बढ़ाने की नई धमकी के बाद अमेरिकी खरीदार उन्हें थोड़े बहुत जो भी आर्डर दे रहे थे, उसे भी रोक देंगे।पिछले छह महीनों से भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने की चर्चा तो चल रही है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला नहीं होने से अमेरिकी खरीदार असमंजस की स्थिति में है। 50 प्रतिशत शुल्क के साथ वे भारतीय निर्यातकों को अधिक आर्डर नहीं दे रहे हैं और शुल्क बढ़ने पर इस आर्डर में और कमी आएगी।

भारत कृषि और डेरी बाजार खोलने को तैयार नहीं

सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका के लिए अपने कृषि और डेरी बाजार को खोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस वजह से भी अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते को टाल रहा है। अमेरिका भारत में अपने जेनेटिकली मोडिफाइड सोयाबीन और मक्के को बेचना चाहता है, लेकिन भारत किसानों के हितों को देखते हुए किसी भी सूरत में इन वस्तुओं की बिक्री की इजाजत देने के पक्ष में नहीं है।

व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका के उतार-चढ़ाव वाले रुख को भारत पहले ही भांप गया था, इसलिए उसने पिछले साल से ही अमेरिका के बाजार में प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई के लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश तेज कर दी थी। इसका नतीजा भी दिखने लगा और अब भारत दुनिया के 200 बाजारों में निर्यात करने लगा है। पिछले साल ब्रिटेन, ओमान व न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया और इस साल इन समझौते पर अमल शुरू हो जाएगा। इससे इन देशों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और भारत का निर्यात बढ़ेगा। अमेरिकी चुनौतियों को देखते हुए भारत निर्यात प्रोत्साहन योजना भी शुरू कर चुका है। टैरिफ की काट अब तक तो सफल रही है लेकिन फिर से टैरिफ बढ़ता है तो उसकी भरपाई के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे।

भारत बना साइबर फ्रॉड का केंद्र : निवेश स्कैम सबसे बड़ा खतरा

छह साल में 52,976 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी

खास खबर

नेशनल कंटेंट सेल

भारत में साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है. डिजिटल इंडिया के दौर में जहां मोबाइल और इंटरनेट ने जिंदगी आसान बनायी है, वहीं ठगों के लिए यह सबसे बड़ा हथियार भी बन गया है. गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह वर्षों में देशभर में साइबर ठगी और धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों से 52,976 करोड़ रुपये से अधिक की रकम लोगों की जेब से निकल चुकी है. इसमें निवेश स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड और साइबर फिशिंग जैसे अपराध शामिल हैं. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार, साल 2025 साइबर अपराध के लिहाज से अब तक का सबसे चिंताजनक वर्ष रहा. सिर्फ इसी साल लोगों ने 19,812.96 करोड़ गंवाये और 21,77,524 से अधिक शिकायतें दर्ज करायी गयीं. 2024 में 22,849.49 करोड़ का नुकसान हुआ था और 19,18,852 मामले सामने आये थे. वहीं 2023 में ठगी की राशि 7,463.2 करोड़ रही और 13,10,361 शिकायतें दर्ज हुईं.

देश के पांच राज्य, जहां सबसे ज्यादा हुए साइबर फ्रॉड

राज्य	कुल नुकसान	दर्ज शिकायतें
महाराष्ट्र	3,203	28,33,200
कर्नाटक	2,413	21,32,280
तमिलनाडु	1,897	12,32,900
उत्तर प्रदेश	1,443	27,52,640
तेलंगाना	1,372	लगभग 95,000

*कुल नुकसान करोड़ रुपये में

हर साल बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी 2025 में रिकॉर्ड नुकसान

विदेशों से चल रहा गिरोह, छोटे शहर भी निशाने पर

जांच एजेंसियों का कहना है कि साइबर ठगी के कई तार विदेशों से जुड़े हुए हैं. संगठित नेटवर्क के जरिये ठग अलग-अलग हिस्सों को निशाना बना रहे. अब साइबर ठगी छोटे शहरों व गांवों में भी फर्जी लोन एप व ज्यादा रिटर्न का लालच देने वाली निवेश योजनाओं के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं.

शहरी इलाकों में ज्यादा मार

अधिकारियों के मुताबिक, शहरी और डिजिटल रूप से ज्यादा जुड़े इलाकों में ठगों की गतिविधियां सबसे अधिक देखने को मिल रही हैं. राज्यवार आंकड़ों में गुजरात में 1,312.26 करोड़, दिल्ली में 1,163 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 1,073 .98 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया. पूर्वोत्तर के मणिपुर में 16 .74 करोड़ की ठगी हुई और 1,807 शिकायतें सामने आयीं. डेटा के अनुसार, कुल नुकसान में से 77 प्रतिशत रकम फर्जी निवेश योजनाओं के नाम पर गंवायी गयी. इसके अलावा आठ प्रतिशत डिजिटल अरेस्ट स्कैम, सात प्रतिशत क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, 4 प्रतिशत सेक्सटॉर्शन, 3 प्रतिशत ई-कॉमर्स फ्रॉड और एक प्रतिशत एप या मालवेयर आधारित ठगी से जुड़ी रही.

जोहानिसबर्ग के बीएपीएस मंदिर में स्थापित हुई गुरु नीलकंठ वर्णी की 42 फुट ऊंची प्रतिमा

एजेंसियां, जोहानिसबर्ग

दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग स्थित बीएपीएस मंदिर परिसर में 18वीं शताब्दी के योगी व आध्यात्मिक गुरु नीलकंठ वर्णी की 42 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गयी है. जोहानिसबर्ग के बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) मंदिर में रविवार को स्थापित की गयी यह प्रतिमा दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है. यह नाइजीरिया के इले-इफे में स्थित मोरेमी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ अफ्रीकी महाद्वीप की संयुक्त रूप से चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा का दर्जा भी रखती है. बीएपीएस ने एक बयान में कहा कि वृक्षासन नामक योग मुद्रा के एक रूप में विराजमान यह प्रतिमा विशाल परिसर के प्रवेश द्वार पर स्थापित है और अनुशासन, युवा आदर्शवाद और आंतरिक संतुलन के एक प्रमुख सार्वजनिक प्रतीक के रूप में कार्य करती है. प्रमुख रूप से तांबे और पीतल से बनी है.

शोध

सूखे की मार से नष्ट हुई सिंधु घाटी सभ्यता

जनसत्ता संवाद

सिंधु घाटी सभ्यता का पतन सदियों तक चले जलवायु संकटों का परिणाम था। नए अध्ययन से पता चला है कि सूखे और घटती बारिश के कारण यह सभ्यता धीरे-धीरे ढह गई। उन्नत जल प्रबंधन और सुनियोजित शहरों के बावजूद, जल संकट ने कृषि को प्रभावित किया और लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस अवधि में औसत तापमान करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, जबकि सालाना बारिश में 10 से 20 फीसद तक की कमी आई।

सदियों पहले भी जलवायु संकट ने इंसानी सभ्यता को प्रभावित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बार-बार पड़े सूखों के कारण धीरे-धीरे नष्ट हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता, जो मौजूदा भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में फैली थी, अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में गिनी जाती थी। यह सभ्यता आज से करीब 5,000 से 3,500 साल पहले अस्तित्व में थी और उसी दौर में थी, जब मिस्र की प्राचीन सभ्यता फल-फूल रही थी।सदियों तक चले जल संकट ने कृषि को नुकसान पहुंचाया, पानी की उपलब्धता घट गई और लोगों को शहर छोड़कर छोटे इलाकों और नए क्षेत्रों की ओर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा।

करीब 4,500 से 3,900 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के शहर बेहद सुनियोजित थे। जल प्रबंधन की उन्नत प्रणालियां, पक्की सड़कें और नालियां इसके शहरों की पहचान थे। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (आइआइटी), गांधीनगर से जुड़े वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन में शोधकर्ताओं जलवायु माडल, गुफाओं में मौजूद स्टैलेक्टाइट-स्टैलेग्माइट की रासायनिक संरचना और उत्तर-पश्चिम भारत की झीलों के जल स्तर के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस अवधि में औसत तापमान करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, जबकि सालाना बारिश में 10 से 20 फीसद तक की कमी आई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ। बल्कि यह लंबे समय तक चले सूखे, घटती बारिश और बदलती जलवायु का नतीजा था। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस अवधि में औसत तापमान करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। सालाना बारिश में 10 से 20 फीसद तक की कमी आई।

(फाइल फोटो)

इस अध्ययन के मुताबिक करीब 4,450 से 3,400 साल पहले कम से कम चार लंबे सूखे पड़े। इनमें से सूखे की हर घटना 85 साल से भी ज्यादा समय तक बनी रही, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के 65 से 91 फीसदी इलाके को प्रभावित किया। यानी ये सूखे किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं थे, बल्कि कई पीढ़ियों ने उनका असर झेला था।

शोधकर्ताओं ने सूखे के दौरान नदियों के बहाव में आए बदलाव के आधार पर इस क्षेत्र को चार अलग-अलग हिस्सों में बांटा। इनमें ऊपरी सिंधु (हड़प्पा क्षेत्र), मध्य सिंधु (कोट दीजी, गणवेरीवाला, कालीबंगन और बनावली), निचला सिंधु (मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो) तथा सौराष्ट्र क्षेत्र (धोलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल) शामिल हैं।

सूखे के दौरान इन क्षेत्रों में पानी की कमी अलग-अलग स्तर पर रही। इसी अंतर ने तय किया कि लोग कहां कृषि कर सकते हैं और कहां बस सकते हैं। उदाहरण के लिए, 3,826 वर्ष पहले और 3,531 वर्ष पहले पड़े सूखों में मध्य सिंधु क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जबकि सौराष्ट्र जैसे बाहरी इलाके अपेक्षाकृत कम प्रभावित रहे।

ये भौगोलिक पैटर्न पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मेल खाते हैं। प्रमाण दिखाते हैं कि अलग-अलग नदी घाटियों में कृषि के तरीके अलग और लगातार एक जैसे रहे, जिससे पता चलता है कि शुरुआती किसान स्थानीय जल उपलब्धता के हिसाब से कृषि करते थे।

Jansatta Page No-7

राष्ट्रमंडल सम्मेलन

राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन लंदन में प्रारंभ हो गया है। यह सम्मेलन दस दिन तक जारी रहेगा। उसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, लंका, दक्षिण रोडेनिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों में केवल पाकिस्तान ही ऐसा है, जिसके प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली ने अभी तक लंदन सम्मेलन में भाग लेने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। श्री लियाकत अली ने यह आग्रह किया था कि लंदन सम्मेलन के विचारणीय विषयों की सूची में काश्मीर के प्रश्न को भी शामिल किया जाये। राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन की मर्यादाओं को सभी जानते हैं। राष्ट्रमंडल एक ढीला-ढाला संगठन है। उसको यह हक हासिल नहीं है कि वह अपने किन्हीं निर्णयों को मानने के लिए सदस्य राष्ट्रों को बाध्य कर सके। वह एक ऐसा मंच है, जहां सदस्य राष्ट्र विचार-विनिमय के लिए एकत्र होते हैं और समान हित से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर पारस्परिक सहयोग स्थापित करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों ने यह परम्परा डाल ली है कि ऐसे मतभेद के विषयों पर, जो दो देशों से संबंध रखते हों, प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा न की जाये। यह परम्परा व्यावहारिक और बुद्धिमानी की सूचक है। यह सब जानते-बूझते हुए भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काश्मीर के प्रश्न को लंदन सम्मेलन की विषय सूची में बाकायदा शामिल करने का आग्रह किया और आग्रह भी इस हद तक कि यदि उसे न माना जाये, तो वह लंदन सम्मेलन का बहिष्कार कर देंगे, आश्चर्य का ही विषय हो सकता है।

काश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के सिपुर्द है। राष्ट्रमंडल संगठन विधिवत इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न भारत को ही यह मंजूर हो सकता है कि वह इस प्रकार हस्तक्षेप करे। यह प्रश्न ऐसा नहीं है, जो राष्ट्रमंडल के देश बहुमत के जोर पर भारत पर दबाव डाल कर हल कर सकें। भारत की इच्छा के विरुद्ध कोई हल उस पर नहीं थोपा जा सकता। राष्ट्रमंडल के देशों की यह स्वाभाविक इच्छा हो सकती है कि मौजूदा नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान लंदन सम्मेलन से अपने को अलग न रखे और उसकी महत्वपूर्ण चर्चाओं में उचित भाग ले।

Hindustan Page

Useful For Mains

जनसंख्या नियोजन

सशक्त समाज की बुनियाद

तेजी से बढ़ती जनसंख्या के दौर में जनसंख्या नियोजन केवल संख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि संसाधनों के संतुलित उपयोग, गुणवत्तापूर्ण जीवन और आत्मनिर्भर समाज की दिशा में कदम है। दैनिक जागरण की उम्मीदें 2026 शृंखला की छठी किस्त में ऐसे ही दो प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। एक ओर, छह दशकों से मूक-बधिर और दृष्टिहीन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित संस्था है, तो दूसरी ओर फर्रुखाबाद की नारायणी देवी हैं, जिन्होंने स्वयं सशक्त होकर 1200 महिलाओं को आजीविका से जोड़ा है। ये दोनों कहानियां बताती हैं कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अवसर ही जनसंख्या नियोजन का स्थायी समाधान हैं।

Dainik Jagaran Page jhankar -17

मैन्यूफैक्चरिंग मिशन से बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के मौके

विश्व के दूसरे देश जहां घटती जन्म दर और उम्रदराज आबादी से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं वहीं भारत युवाओं की बड़ी जनसंख्या के साथ अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहा है। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए बजट 2025-26 में जरूरी संसाधन का आवंटन किया गया है। बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग मिशन शुरू करने की घोषणा भी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। उम्मीद है कि 2026 में मैन्यूफैक्चरिंग मिशन बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देगा।

4,73,1,115 करोड़ युवा प्रशिक्षण पूरा करके काम कर रहे हैं स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत

2,41,2,925 करोड़ युवा पूरा कर चुके हैं कौशल विकास प्रशिक्षण

9,36,786 युवा वर्तमान में हासिल कर प्रशिक्षण

वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रही है देश की युवा आबादी

भारत की बड़ी 27 प्रतिशत युवा आबादी, जिसे आमतौर पर जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है, इसे वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की युवा पीढ़ी कल के नवप्रवर्तक, निर्माता, विकासकर्ता और नेता हैं। यदि उन्हें कौशल विकास, ज्ञान और अवसर प्रदान किए जाएं तो वे परिवर्तन और विकास की एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं। वैश्विक निवेशकों के लिए अवसर यहीं निहित है। प्रशिक्षित और प्रशिक्षण योग्य श्रमिकों के विशाल भंडार तक पहुंच भविष्य के आर्थिक विकास और क्रय शक्ति में वृद्धि के अवसर पैदा कर सकती है। जैसे-जैसे यह युवा पीढ़ी कार्यबल में प्रवेश करेगी और खर्च करने योग्य आय अर्जित करेगी, यह विभिन्न व्यवसायों में घरेलू खर्च को समर्थन देना जारी रखेगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर होगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

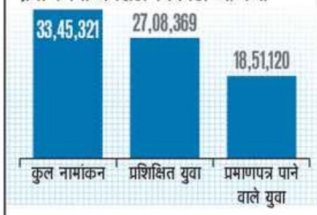

37.14 करोड़ युवा हैं भारत में, जो कुल आबादी का लगभग 27 प्रतिशत हैं

25 वर्ष से कम आयु के हैं भारत में 10 में से 4 से अधिक लोग

20 लाख अंग्रेजी भाषी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) स्नातकों का सबसे बड़ा समूह भारत में है

1.8 करोड़ एसटीईएम स्नातक होंगे, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2027 तक देश में लगभग

1,70,000 से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं भारत में, जो इसे वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करते हैं।

24.3% हिस्सा भारत से आएगा वैश्विक कार्यबल में होने वाली वृद्धि का ईवाई के अनुमान के अनुसार

42.6% थी 2021-22 में कुल एसटीईएम स्नातकों में महिलाओं की हिस्सेदारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार, 2021-22 में

68.9% पर पहुंच जाएगा भारत की कुल जनसंख्या में कामकाजी आयु वर्ग की जनसंख्या का हिस्सा 2030 तक अपने उच्चतम स्तर

31.2% पर पहुंचने का अनुमान है 2030 तक भारत का आश्रितता अनुपात अपने सबसे निचले स्तर

Dainik Jagaran Page jhankar -17

प्रदेश में रोजगार की राह खोलेगा मेगा स्किल सेंटर

पहल

विद्या सागर ● जागरण

पटना : राज्य सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष से राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की शुरुआत होगी, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने के साथ ही प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना को सात निश्चय पार्ट-3 के तहत लागू किया जाएगा। पहले मेगा स्किल सेंटर प्रमंडल स्तर पर खोलने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे जिला स्तर तक विस्तारित करने

प्रमुख इंडस्ट्रीज को आपस में जोड़ कर उनकी जरूरत के अनुसार तैयार किए जाएंगे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

कौशल किशोर, सचिव, युवा, रोजगार व कौशल विकास विभाग ● जागरण

का निर्णय लिया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। साथ ही कई प्रमुख इंडस्ट्रीज को इससे जोड़ने पर बातचीत चल रही है, ताकि उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकें।

मेगा स्किल सेंटर में इंडस्ट्री की वर्तमान जरूरत के अनुसार कोर्स डिजाइन किए जाएंगे। पारंपरिक ट्रेड के बजाय आइटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नई तकनीकों पर आधारित कोर्स संचालित किए जाएंगे। शुरुआत में आइटी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिव कौशल किशोर ने बताया कि तकनीकी बदलाव के इस दौर में युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।

नियोजनालय को पूरी तरह ई-मोड में लाने की तैयारी

सभी जिलों में संचालित 100 लोगों की क्षमता वाले करियर इंफार्मेशन सेंटर को भी आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को करियर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण विकल्पों और रोजगार की जानकारी एक ही छत के नीचे मिलेगी। नियोजनालय को पूरी तरह ई-मोड में लाने की तैयारी है, जिससे सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी हो सकें। राज्य सरकार युवाओं को विदेशों में नौकरी उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही है। इसका लाभ शीघ्र ही दिखने लगेगा।

****

Dainik Jagaran Page No-15

मंथन

युवा अपेक्षाओं से जुड़ी चुनौतियां

ऋषभ मिश्र
असिस्टेंट प्रोफेसर, कानपुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर

वर्ष 2022 में शहरी बेरोजगारी दर 14.3 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2025 में लगभग नौ प्रतिशत पर आने का अनुमान है, परंतु इस तस्वीर का दूसरा पहलू कहीं अधिक चिंताजनक है

प्रतीकात्मक

देश के शहरी क्षेत्र में रोजगार की स्थिति तेजी से बदली है। इसके आंकड़े उम्मीद और चिंता दोनों सामने लाते हैं। वित्त वर्ष 2022 में जहां शहरी बेरोजगारी दर 14.3 प्रतिशत थी, वहीं 2025 में इसके नौ प्रतिशत पर आने का अनुमान है। यह गिरावट अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि महामारी के दौरान शहरी क्षेत्रों में रोजगार पर सबसे गहरा असर पड़ा था। कार्यालय बंद हुए, सेवा क्षेत्र ठप पड़ा और लाखों लोग या तो काम से बाहर हो गए या उन्हें गांवों की ओर लौटना पड़ा। ऐसे में कुल शहरी बेरोजगारी दर में यह सुधार अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का संकेत देता है।

इस सुधार में महिलाओं की भूमिका खास तौर पर उल्लेखनीय रही है। उपलब्ध श्रम बल सर्वेक्षणों के अनुसार शहरी महिला कार्यबल भागीदारी दर पिछले तीन वर्षों में लगातार बढ़ी है। महामारी से पहले जहां शहरी महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी लगभग 20 से 21 प्रतिशत के आसपास थी, वहीं अब यह 25 प्रतिशत के लगभग पहुंच रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रिटेल, घरेलू सेवाओं, आइटी सपोर्ट और गिग इकोनमी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नए अवसर बने हैं, जबकि प्राम होम ने भी कई महिलाओं को कमाई करने का मौका दिया है।

यही कारण है कि शहरी बेरोजगारी दर में आई गिरावट का एक बड़ा हिस्सा महिला रोजगार में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। इस तस्वीर का दूसरा पहलू कहीं अधिक चिंताजनक है। शहरी युवाओं की बेरोजगारी दर अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 16.8 प्रतिशत है। यह दर कुल शहरी बेरोजगारी दर से लगभग दोगुनी है। यानी अर्थव्यवस्था में पैदा हो रहे रोजगार युवाओं की उस अनुपात में नहीं मिल पा रहे हैं जिस अनुपात में वे श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

हर साल देश में लगभग एक करोड़ युवा कामकाजी आयु में पहुंचते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश करता है। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ने के कारण स्नातक और परास्नातक युवाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले दस वर्षों में उच्च शिक्षा में नामांकन 75 प्रतिशत तक बढ़ा है। इसके बावजूद हम उद्योग और सेवा क्षेत्र में इतनी संख्या में नौकरियां पैदा नहीं कर पाए हैं, जो इन शिक्षित युवाओं को समाहित कर सके।

कौशल व मांग के बीच असंतुलन

: शहरी युवा बेरोजगारी का एक कारण कौशल और मांग के बीच असंतुलन भी है। कई सर्वेक्षण बताते हैं कि निजी क्षेत्र के लगभग 45 से 50 प्रतिशत नियोक्ता नए स्नातकों को तुरंत रोजगार योग्य नहीं मानते हैं। उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण देना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ती है। परिणामस्वरूप कंपनियां या तो अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता देती हैं या फिर आटोमेशन और तकनीक के जरिए काम चलाने का विकल्प चुनती हैं। इससे 'एंट्री लेवल' नौकरियों की संख्या घटती जा रही है, जो युवाओं के लिए रोजगार का पहला कदम होती है।

साथ ही शहरी युवाओं की अपेक्षाएं भी रोजगार संकट को जटिल बनाती हैं। वे अधिकतर स्थायी, सामाजिक सुरक्षा वाली और सम्मानजनक आय देने वाली नौकरियों की तलाश में रहते हैं। 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों' से संकेत मिलता है कि शहरी युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक और कम वेतन वाले काम को अस्थाई समाधान के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहता। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध रोजगार का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक प्रकृति का है, जहां आय और सुरक्षा सीमित होती है।

शहरी युवा बेरोजगारी के सामाजिक प्रभाव भी गंभीर हैं। लंबे समय तक बेरोजगार रहने वाले युवाओं में मानसिक तनाव, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी की आशंका अधिक होती है। लिहाजा नीतिगत स्तर पर इस स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। शहरी युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित न रखकर उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। अप्रेंटिसशिप और 'आन द जाब ट्रेनिंग' को उद्योग के साथ जोड़कर वास्तविक रोजगार के अवसरों में बदला जाना चाहिए। निजी क्षेत्र को युवाओं की भर्ती के लिए प्रोत्साहन देने वाले उपाय जैसे वेतन सब्सिडी या कर राहत भी रोजगार सृजन में सहायक हो सकते हैं।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी जरूरी है। शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों को तेजी से बदलते रोजगार बाजार के अनुरूप बनाना होगा। डिजिटल कौशल, डाटा विश्लेषण, ग्रीन टेक्नोलाजी जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है। साथ ही शहरी युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना और उन्हें ऋण मेंटरशिप और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना भी बेरोजगारी के दबाव को कम कर सकता है।

Dainik Jagaran Page No-9

'हंड्रेड मिलियन जॉब्स' नामक एक राष्ट्रीय पहल की हुई शुरुआत

उद्योग जगत की पहल, अगले दशक मिलेंगे रोजगार के 10 करोड़ अवसर

एजेंसियां, नयी दिल्ली

देश में नौकरियों को लेकर उद्योग जगत ने एक नयी पहल की है. उद्योग जगत के दिग्गजों के एक समूह ने सोमवार को 'हंड्रेड मिलियन जॉब्स' (10 करोड़ नौकरियां) नामक एक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की है. इस पहल का उद्देश्य आगामी दशक में भारत में 10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है, क्योंकि देश तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद अपर्याप्त रोजगार की समस्या से जूझ रहा है. आयोजकों ने एक बयान में कहा कि इस मुहिम की घोषणा सॉफ्टवेयर उद्योग निकाय नैसकॉम के सह-संस्थापक हरीश मेहता, वैश्विक उद्यमी नेटवर्क 'द इंडस एंटरप्रेन्योर्स' (टीआइइ) के संस्थापक एजे पटेल और सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी के संस्थापक के यतीश राजावत ने की. संस्थापकों ने कहा कि भारत में कार्यशील आयु की जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 1.2 करोड़ की दर से बढ़ रही है.

रोजगार सृजन को वृद्धि का एक मुख्य मानक बनाना है लक्ष्य

'हंड्रेड मिलियन जॉब्स' मिशन उद्यमिता, कौशल विकास और श्रम-प्रधान उद्यमों को भारत की रोजगार रणनीति के केंद्र में रखता है. इस पहल का लक्ष्य रोजगार सृजन को आर्थिक वृद्धि का एक मुख्य मानक बनाना है, जिसका ध्यान विभिन्न क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत और सुदृढ़ आजीविका सुनिश्चित करने पर होगा.

रोजगार की वृद्धि दर उत्पादन विस्तार की तुलना में है पीछे

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बाद भी भारत में रोजगार की वृद्धि दर उत्पादन विस्तार की तुलना में पीछे रही है. स्वचालन और कृत्रिम मेधा (एआइ) व्यापार के तौर-तरीकों को बदल रहे हैं और कई क्षेत्रों में शुरुआती स्तर के पदों को कम कर रहे हैं. ऐसे में यह चिंता बढ़ गयी है कि आर्थिक वृद्धि रोजगार सृजन से पूरी तरह कट सकती है.

अगली पीढ़ी के लिए गरिमापूर्ण आजीविका होगी सुनिश्चित

नैसकॉम के सह-संस्थापक हरीश मेहता ने कहा, 'हंड्रेड मिलियन जॉब्स' रोजगार के अवसर पैदा करने वाले – उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों और नियोक्ताओं – को मजबूत करने का एक व्यवस्थित प्रयास है. इसके तहत कौशल, उद्यम, डेटा और नीति में सामंजस्य बिठाकर अगली पीढ़ी के लिए लचीली और गरिमापूर्ण आजीविका सुनिश्चित की जायेगी. टीआइइ के संस्थापक एजे पटेल ने कहा कि स्टार्टअप और लघु उद्योग, जो भारत के जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देते हैं और सबसे बड़े नियोक्ता हैं, उनका विस्तार बड़े शहरों से आगे होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर भारत को प्रतिवर्ष 80-90 लाख नौकरियां सुलिट करनी हैं, तो कुछ ढांचागत बाधाओं को दूर करना होगा.

Prabhat khabar Page No-16

उच्च शिक्षा की समस्याओं का समाधान

केवल डिग्री हासिल कर लेने को शिक्षा नहीं कह सकते। शिक्षा वह शक्ति है, जो जीवन को दिशा देती है। सफल शिक्षा एक व्यक्ति के सोचने का तरीका बदल सकती है, उसे जीवन उद्देश्य दे सकती है और अपने भीतर छिपी संभावनाएं पहचानने का अवसर दे सकती है। खासतौर पर उच्च शिक्षा वह पड़ाव है, जहां युवा अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानते हैं और भविष्य की राह खोजने की शुरुआत करते हैं। जहां एक तरफ स्कूली शिक्षा हमें हमारे आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है, वहीं उच्च शिक्षा छात्रों को अपने विकल्प जानने की आजादी देती है। उच्च शिक्षा समय है अलग-अलग विषयों और क्षेत्रों को समझने और यह तय करने का कि उन्हें जीवन में क्या करना है। यह प्रक्रिया सरल नहीं, जटिल होती है। एक छात्र के आजादी से अपनी राह चुन सकने के पीछे एक मजबूत संस्थान, संसाधन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।

भारत जैसे विशाल और विविध देश में संस्थान निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है। हर साल लाखों छात्र स्कूलों से निकलकर उच्च शिक्षा की ओर रुख करते हैं, लेकिन संस्थानों में इतनी सीटें ही नहीं कि सबको दाखिला मिल सके। नतीजतन प्रतिस्पर्धा और तेज होती जा रही है और परीक्षाएं और ज्यादा मानकीकृत हो रही हैं। इस सबके साथ-साथ व्यवस्था अक्सर प्रशासनिक सुविधा की सहूलियत देखती है। इस गहन माहौल में हर छात्र की अलग पहचान और क्षमता पर ध्यान दे पाना असंभव हो जाता है। आज भारत में लगभग 70,018 उच्च शिक्षा संस्थान हैं। भले ही यह उत्साहजनक लगे, लेकिन देश की जरूरतों के मुकाबले अभी भी पर्याप्त नहीं। युवावर्ग अब भी बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा खोज रहा है। आपूर्ति की कमी का असर छात्र के इस निर्णय पर पड़ता है कि वह कहां पढ़े। सख्त आव्रजन नीतियों के बाद भी भारतीय छात्र बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने जा रहे हैं। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन उनके प्रमुख गंतव्य हैं। हालांकि अब फ्रांस, आयरलैंड और इटली भी तेजी से छात्रों में लोकप्रिय हो रहे हैं।

प्रमथ राज सिन्हा

नए पाठ्यक्रम, बेहतर तकनीक और उद्योग से पढ़ाई को जोड़कर भारतीय संस्थान खुद को मजबूत बना सकते हैं

समय की आवश्यकता के अनुरूप बने शिक्षा ● फहल

जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 12 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। इस आंकड़े से घरेलू स्तर पर आवश्यकता और सीमित विकल्प साफ उजागर होते हैं। इन चुनौतियों के बीच से ही बड़े अवसर भी उत्पन्न होते हैं।

तेजी से बदलती दुनिया में पहला अवसर नवाचार में निहित है। भारत में हमें अधिक बहुविषयक कार्यक्रमों की आवश्यकता है। हमें ऐसे कार्यक्रमों के बारे में सोचना होगा, जो तकनीक, पर्यावरण, सूचना और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हों। मैनेजमेंट, कानून और मेडिकल जैसे पारंपरिक कोर्स को भी नए ढंग से देखना होगा। नए पाठ्यक्रम, बेहतर तकनीक और उद्योग से पढ़ाई को जोड़ कर भारतीय संस्थान खुद को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना सकते हैं। दूसरा बड़ा अवसर है, डिजिटल शिक्षा। हाइब्रिड माडल प्रभावी हो सकते हैं, जिन्हें आनलाइन और आफलाइन पढ़ाई को मिलाकर बनाया गया हो। अगर सही ढंग से लागू किए जाएं तो ये बड़े पैमाने पर लाभकारी शिक्षा का साधन बन सकते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहां छात्र दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, डिजिटल शिक्षा एक असरदार समाधान प्रस्तुत करती है। अपने सशक्त डिजिटल ढांचे की सहायता से भारत विश्व के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है, और उसे ऐसा करना भी चाहिए। नीतिगत स्तर पर आज सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। तीन दशक बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों का बीड़ा उठाया है। बहुविषयक पढ़ाई, विषयों में लचीलापन और संस्थानों की स्वायत्तता जैसे विचारों पर अब जोर दिया जा रहा है। दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के पूर्व अनुभव बताते हैं कि जब-जब सरकारें शोध, नवाचार और तकनीक को शिक्षा का केंद्र बनाती हैं, तब-तब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। तीसरा अहम पहलू है, प्रतिभा निर्माण। उच्च शिक्षा संस्थान का उद्देश्य केवल रुखा ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों के सोच के दायरे को विस्तार देना, कौशल को बढ़ाना और छात्रों को पेशेवर समझ देना भी है। सार्थक शिक्षा देश को ऐसा मानव संसाधन देती है, जो न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने क्षमता रखता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आत्मविश्वास के साथ अपना योगदान दे सकता है।

अगर हम पीछे मुड़ कर देखेंगे तो पाएंगे कि उच्च शिक्षा की परंपरा हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। अपने-अपने समय में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्र विश्व भर से विद्वानों को आकर्षित करते रहे। इन सभी ने जिज्ञासा एवं शोध को शिक्षा का मूल सिद्धांत बनाया। आज भले ही समय और परिस्थितियां बदल गई हों, लेकिन हमारा लक्ष्य और भी स्पष्ट है। अगर हमें 2035 तक सकल नामांकन का अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है और केवल डिग्री पर केंद्रित न रह कर सीखने की सामर्थ्य को प्रोत्साहित करना है तो संस्थान निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। हमारे आज के प्रयास से भारत के शिक्षा संस्थान न केवल युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं को सही दिशा दे सकेंगे, बल्कि यही युवा आगे चलकर विकसित भारत 2047 की नींव भी मजबूत करेंगे।

(लेखक अशोका यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन, बोर्ड आफ ट्रस्टी हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

असभ्य सामग्री पर लगाम आवश्यक

डा. मोनिका शर्मा

हाल में भारत सरकार द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए जारी किए गए नोटिस को इस वर्चुअल मंच के मालिक एलन मस्क ने गंभीरता से लिया है। मस्क ने एक्स के एआइ टूल 'ग्रोक' के माध्यम से अश्लील कंटेंट बनाने वाले यूजर्स को कड़ी चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से एलन मस्क की कंपनी को इसी एआइ टूल के जरिये महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने और साझा करने की शिकायतों के बाद यह नोटिस जारी किया गया था। महिलाओं से जुड़ी अश्लील, अभद्र और यौन प्रकृति की सामग्री तथा एक्स पर फैल रही असभ्य प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया यह कदम महिलाओं की निजता, गरिमा और सुरक्षा से सीधे जुड़ा है। दुखद तथ्य यह है कि तकनीकी सुविधाओं के सकारात्मक और विवेकपूर्ण उपयोग के बजाय कुछ लोग उनके नकारात्मक प्रयोग के रास्ते तलाश

सरकार ने 'एक्स' से सभी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं, जो महिलाओं की गरिमा तार-तार कर रहे हैं

लेते हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर उपलब्ध अनेक टूल्स ऐसे उपयोगकर्ताओं की दूषित मानसिकता का हथियार बन जाते हैं। यह समझना कठिन नहीं कि असभ्य और आपत्तिजनक सामग्री तैयार करने के कुत्सित सोच का सबसे पहला शिकार महिलाएं ही बनती हैं। एक्स पर भी महिलाओं की छवियों के साथ छेड़छाड़ कर अभद्र कंटेंट तैयार किया जा रहा था। इसी कारण सरकार ने एक्स प्लेटफार्म से सभी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए।

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि 'ग्रोक' का दुरुपयोग महिलाओं की गरिमा और निजता के अधिकार के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, इस तरह की गतिविधियां कानूनी सुरक्षा उपायों को भी कमजोर करती हैं। यही कारण है कि सरकार ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। वास्तव में 'ग्रोक' का दुरुपयोग आम हों या खास-सभी महिलाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सामाजिक छवि धूमिल करने से लेकर मानसिक पीड़ा पहुंचाने तक, इस तरह की सामग्री महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान में बाधा बनती है।

निस्संदेह महिलाओं की अशोभनीय छवियां बनाकर एक्स पर साझा करना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। सरकार ने एक्स को चेतावनी दी है कि यह मंच आइटी एक्ट, 2000 और आइटी नियम 2021 के तहत अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में असफल रहा है। ऐसे में एलन मस्क का यह स्पष्ट संदेश कि ग्रोक के जरिये गैरकानूनी एवं आपत्तिजनक कंटेंट बनाने या अपलोड करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, स्वागतयोग्य है। इंटरनेट मीडिया के मनमाने दुरुपयोग और असभ्य सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार की यह सख्ती समय की मांग है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

साम्राज्यवाद का प्रतिरोध आवश्यक

श्रीराम चौलिया

सभ्य विश्व व्यवस्था तभी संभव है, जब कमजोर देश एकजुटता से महाशक्तियों की मनमानी का विरोध करें। यदि साम्राज्यवाद सदियों पुराना है तो समानता और मर्यादा की चाह भी उतनी ही पुरानी है

वेनेजुएला में अमेरिकी हमला यही दर्शाता है कि हम महाशक्तियों की घातक प्रतिस्पर्धा और उनके मनमाने हस्तक्षेपों के दौर में जी रहे हैं। ऐसे दौर में जहां अंतरराष्ट्रीय कानूनों और जंगल के कानूनों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। वेनेजुएला में तख्तापलट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी बघारते हुए कहा, 'हमें इसे फिर से करना होगा, हम फिर से ऐसा कर सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता।' यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। ट्रंप का यह औपनिवेशिक दावा कि 'हम वेनेजुएला को चलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे ठीक से चलाया जाए', स्पष्ट संकेत है कि शक्तिशाली ही शक्तिहीन पर राज करेंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला में अवैध रूप से सत्ता परिवर्तन करके वहां के खनिजों को अमेरिकी कंपनियों के एकाधिकार में लाने की खुलेआम घोषणा से सिद्ध कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के जो भी बचे-कुचे बंधन थे, वे भी ध्वस्त होते जा रहे हैं। इससे पहले रूस ने अपने मुकाबले कमजोर पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण कर उस पर विशेषाधिकारों का दावा किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार बड़ी शक्तियों को अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्र रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और यूक्रेन की सच्ची संप्रभुता तभी संभव है जब वह रूस के प्रति मित्रवत और पराधीन रहे। इनके उलट चीन ने अभी तक ताइवान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने या भारत, वियतनाम, फिलीपींस अथवा जापान पर सीधे हमले का प्रयास नहीं किया है, परंतु कमजोर पड़ोसियों के प्रति उसका भी औपनिवेशिक और दबंग रवैया है जो दिन-प्रतिदिन और बिगड़ता जा रहा है। जब सभी बलशाली देश आक्रामक और लुटेरे तेवरों पर उतर आएं तो बड़ी मछली का छोटी मछली को निगलना सामान्यीकृत होने लगता है।

वैश्विक राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वह सिद्धांतों एवं मानदंडों के आधार पर संचालित होती है, लेकिन हालिया उदाहरण कुछ और ही संकेत करते हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद ताइवान को लेकर समय-समय आक्रामकता दिखाने वाले चीन पर भी अंतरराष्ट्रीय कानून वाले तर्क बेमानी हो जाते हैं। लैटिन भाषा में 'टू कुआकवे' जैसी एक संकल्पना है, जिसके अनुसार प्रतिद्वंद्वी के व्यक्तिगत व्यवहार और कार्यों को उनके तर्क के साथ असंगत बताकर उनके तर्क को अमान्य कर दिया जाता है। वेनेजुएला में सशस्त्र हमला कर और उसकी आंतरिक राजनीति को जबरदस्ती बदलकर ट्रंप ने हर संभावित हमलावर को सुविधाजनक बहाना दे

अवधेश राजपूत

दिया है। ट्रंप प्रशासन की नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका पर प्रभुत्व स्थापित करने और एक ऐसे पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण करने के लिए उन्नीसवीं सदी के 'मोनरो सिद्धांत' को समकालीन संदर्भ में लागू करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की सरकारों को अमेरिका के आर्थिक और सामरिक हितों के अनुसार चलना होगा। अगर लैटिन अमेरिका में अमेरिका की धौंस जायज है, तो एशिया में चीन अपने आप को बेताज बादशाह क्यों न मान ले?

देखा जाए तो ताइवान का परिप्रेक्ष्य वेनेजुएला से भिन्न है, मगर जब संप्रभुता और शांतिपूर्वक बर्ताव के सिद्धांत ही लुप्त हो रहे हों तो राष्ट्रपति शी चिनफिंग जैसे आक्रामक नेता अराजकता का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? चीन निश्चित रूप से इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और अब वेनेजुएला में पश्चिमी दखलंदाजी का हवाला देकर ताइवान और अन्य एशियाई पड़ोसियों पर दबाव और हमले की योजनाओं को तेज करेगा। रूस की तरह चीन भी कहता आ रहा है कि पश्चिमी शक्तियों के पाखंड और दोहरे रवैये के कारण ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों के चिथड़े उड़ गए हैं और वे तीनों अपनी 'आत्मरक्षा' के नाम पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वयं को विवश बताते हैं। ताइवान को धमकाने के लिए चीन द्वारा किए जा रहे प्रत्येक युद्ध अभ्यास में अनिश्चितता अंतर्निहित है और इनमें से कोई भी वास्तविक युद्ध में तब्दील हो सकता है।

अब तक अगर ताइवान पर चीन ने धावा नहीं बोला है तो यह अंतरराष्ट्रीय नियम या विधि के प्रति शी चिनफिंग की श्रद्धा के कारण नहीं है, बल्कि उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा की वजह से है जब हिंद-प्रशांत में शक्ति संतुलन और भूराजनीतिक परिस्थितियां चीन के पक्ष में कहीं अधिक झुक जाएं। चीन भली-भांति जानता है की अमेरिका अब भी 'खुले एवं स्वतंत्र' हिंद-प्रशांत को अपना मूल राष्ट्रीय हित मानता है और अमेरिकी सैन्य सामग्री लगातार ताइवान तथा अन्य एशियाई मित्र देशों को बेची भी जा रही है। चिनफिंग यह चाहेंगे कि वेनेजुएला में हस्तक्षेप के बाद अगर अमेरिका उसी पड़ोसी क्षेत्र में उपनिवेशवादी मंशा से ज्यादा उलझ जाए और चीन के साथ व्यापार समझौते के चलते एशिया की तकदीर चीन के हाथों छोड़ दें तो ताइवान पर आधिपत्य का उसके पास सुनहरा मौका होगा।

आक्रामक महाशक्तियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर किए जा रहे व्यापक आघातों के मद्देनजर छोटे देशों के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखने की क्या रणनीति हो सकती है? मौलिक स्तर पर उन्हें समूचे 'वैश्विक दक्षिण' में एकजुट होकर हस्तक्षेप की नितांत अस्वीकृति के सिद्धांत पर जोर देना होगा, ताकि महाशक्तियों का जंगल-राज एक सामान्य दस्तूर न बन जाए। व्यावहारिक स्तर पर उन्हें क्षेत्रीय एकीकरण और एकता को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि कोई भी महाशक्ति आसानी से उनमें भेद पैदा करके उन्हें बांट न सके। वेनेजुएला में मादुरो ने सबसे बड़ी भूल यह की कि पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देशों के साथ उन्होंने वर्षों से दुश्मनियां मोल लीं और अंत में अमेरिकी आक्रमण को टालने के लिए कोई प्रांतीय गठबंधन या संस्थान शेष नहीं रहा। स्मरण रहे कि एक सभ्य विश्व व्यवस्था का निर्माण तभी संभव है, जब कमजोर देश एकजुट होकर वर्चस्व का विरोध करें। इतिहास से हम थोड़ी बहुत सीख-समझ भी ले सकते हैं कि यदि साम्राज्यवाद सदियों पुराना है तो समानता और मर्यादा की चाह भी उतनी ही पुरानी है।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page -8

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करने होंगे नए सुधार

जागरण विमर्श

रवि पात ● जागरण

प्रो. विकास सिंह। जागरण

- अर्थशास्त्री प्रो. विकास सिंह बोले, जीएसटी व इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद नए रिफार्म की जरूरत
- कहा- अगले पांच वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आम नागरिकों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा
- एग्रीकल्चर रिफार्म के जरिये जीडीपी में योगदान 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 से 23 प्रतिशत तक लाना होगा

रेयर अर्थ मटीरियल पर निवेश का समय अच्छा

रेयर अर्थ पर चर्चा करते हुए प्रो. सिंह ने बताया कि देश ने रेयर अर्थ पर निर्भरता को कम करने के लिए सही समय पर कदम उठाए हैं। ट्रंप टैरिफ और चाइना से फिलहाल किसी भी मोर्चे पर उलझने की बजाय सरकार इसमें निवेश पर फोकस कर रही है। इसका असर अगले चार से पांच वर्षों में देखने को मिलेगा।

नोएडा: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को अर्थव्यवस्था को मजबूती और रफ्तार के साथ आगे लेकर जाना होगा। आय कर में 12 लाख रुपये तक आय को टैक्स फ्री और जीएसटी दरों को कम करने के बाद अब नए रिफार्म की जरूरत है। अगले पांच वर्षों में देश के आम आदमी को स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देन होगा। देश के करीब 70 प्रतिशत कर्मचारियों समेत गिग वर्कर्स का करीब 95 प्रतिशत खर्च रोजमर्रा की जरूरतों पर हो रहा है। ये वक्तव्य अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा के दौरान दैनिक जागरण के राष्ट्रीय विमर्श कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आइआइपीए) के प्रोफेसर व अर्थशास्त्री विकास सिंह ने कही। इसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती, टैरिफ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने जैसे विषयों पर अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि देश की डेमोग्राफी यानी भारत में युवाशक्ति की कमी नहीं है। वर्ष 2035 तक देश के युवा अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान करेंगे।

फिलहाल, देश की इकोनमी लोअर इनकम इकोनमी है, इसे मिडिल इनकम इकोनमी तक ले जाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। चाइना, ब्राजील जैसे देश मिडिल इनकम इकोनमी तक ही पहुंच पाए हैं। वर्ष 2025 से चाइना की डेमोग्राफी में कमी होने के साथ ही उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट में भी कमी आई है, लेकिन भारत के पास अगले 10 वर्षों तक सुनहरा अवसर है। हाई इनकम इकोनमी भी भारत बन सकता है। विकास सिंह ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इकोनमी में रिफार्म पर जोर दिया।

लैंड रिफार्म से बढ़ सकती है जीडीपी : प्रो. विकास सिंह ने बताया कि देश में लैंड रिफार्म के जरिये किसानों की इकोनमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। मौजूदा वक्त में किसानों का इकोनमी में योगदान 16 प्रतिशत है। रिफार्म के जरिये इसे बढ़ाकर 22 से 23 प्रतिशत तक किया जा सकता है। इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ सात प्रतिशत से बढ़कर नौ प्रतिशत तक हो सकती है। नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा मिल सकता था, उसे समझने की जरूरत है। फरवरी में पेश होने वाले बजट पर सरकार इस मुद्दे पर जरूर ध्यान देगी।

ट्रंप टैरिफ से देश की इकोनमी पर असर नहीं : प्रो. सिंह ने बताया कि देश में लगाए गए ट्रंप टैरिफ से देश की इकोनमी पर खास प्रभाव नहीं पड़ा है। देश का निर्यात यूएस में 2.5 प्रतिशत है, लेकिन बढ़ी टैरिफ की दरों को देखते में कम करने के लिए अमेरिका से बातचीत जारी रखनी होगी। टैरिफ दरें कम होने से भारत का एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। देश की करीब 60 फीसदी इकोनमी डोमेस्टिक है। ट्रंप के टैरिफ का चीन और पश्चिमी देशों पर ज्यादा प्रभाव है।

एमएसएमई को और बढ़ावा देना होगा : देश में करीब सात करोड़ एमएसएमई उद्यमी हैं। करीब 99 प्रतिशत छोटे उद्यमी में एक या दो कर्मी को काम कर रहे हैं। जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 29 से 30 प्रतिशत है, जबकि एक्सपोर्ट में 25 से 30 प्रतिशत योगदान है। प्रो. सिंह ने बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि एमएसएमई व देश की बड़ी कंपनियों के बीच बड़ा खालीपन है। एमएसएमई को बढ़ावा देकर इस खालीपन को भरकर बड़ी कंपनियों से प्रतियोगिता करानी होगी।

नए क्षेत्रों को आगे लाना होगा : प्रो. सिंह ने बताया कि देश में मैन्यूफैक्चरिंग से अब ज्यादा नौकरी नहीं मिल रही है। पहले एक करोड़ रुपये के निवेश से सात नौकरी मिल रही थी, अब ये घटकर चार रह गई हैं। इसलिए नए क्षेत्रों को आगे लाना होगा। देश में कंस्ट्रक्शन कंपनी, टूरिज्म और ट्रेवल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक भी बड़ी इंडस्ट्री निफ्टी में लिस्टेड नहीं है। इन क्षेत्रों को संगठित तौर पर आगे लाना होगा।

Dainik Jagaran Page -5

विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

आजकल

वेनेजुएला संकट के बीच भारत के हित

वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का प्रभाव विश्व के कई हिस्सों पर पड़ना स्वाभाविक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संस्थापक सदस्य वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला करके दुनिया को संदेश दिया है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई हो या उससे जुड़ी राजनीति, अमेरिका की उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह समझना महत्वपूर्ण हो गया है कि इस घटनाक्रम का भारत के हितों पर क्या असर पड़ सकता है और किस प्रकार से यह एक नई वैश्विक ऊर्जा प्रणाली को स्थापित कर सकता है

कच्चे तेल का विश्व का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में है। चीन उसके तेल के बड़े खरीदारों में शामिल है। फाइल

भारत ने वेनेजुएला में घटित घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की है और यह चिंता स्वाभाविक भी है। भारत ने सभी पक्षों से इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान संवाद के जरिए करने की अपील की है। भारत के कई स्ट्रैटेजिक और नान स्ट्रैटेजिक हित इस क्षेत्र में हैं जिनकी उपेक्षा भारत नहीं कर सकता। यदि भारत को दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और लैटिन अमेरिका में अपनी आर्थिक उपस्थिति को मजबूत करना है तो उसे वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया जैसे देशों के साथ संबंध बेहतर करने होंगे, ताकि भारत को अपने इलेक्ट्रानिक व्हीकल मिशन को बढ़ाने के लिए लिथियम आयन बैटरी की आवश्यकता को पूरा करने का रास्ता साफ हो सके। लिथियम ट्राइएंगल दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ही स्थित है, जहां वेनेजुएला संकट चल रहा है।

यहां इस बात का भी उल्लेख होना आवश्यक है कि दक्षिण अमेरिका में जो सबसे बड़ा क्षेत्रीय और व्यापारिक संगठन मर्कोसुर (छह देशों का संगठन जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना आदि शामिल हैं) है, भारत का उसके साथ वरीयतामूलक व्यापार समझौता है। भारत कालांतर में मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी सोच सकता है, लेकिन वेनेजुएला जैसी राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण प्रक्रियाओं पर पड़ना स्वाभाविक है। वेनेजुएला का दुनिया के कच्चे तेल उत्पादन में 0.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। वर्ष 2023 में उसने दुनिया को प्रतिदिन 90 लाख बैरल तेल निर्यात किया। चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। वहीं भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है और पीक लेवल पर चार लाख बैरल तेल प्रतिदिन आयात करता रहा है और ऐसा तब तक चला, जब तक अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध नहीं लगा दिया।

तेल का सबसे बड़ा भंडार : ऐसा माना जा रहा है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद बाजार संकट गंभीर होगा, अवसंरचनाएं कमजोर होंगी, वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है और आयात बिल के लिए भी यह स्थिति खतरनाक होगी। भारत द्वारा संचालित कंपनियों ने वेनेजुएला पर 2020 में अमेरिकी प्रतिबंध लगने के पहले वहां 2.5 अरब डालर का निवेश किया हुआ था। ये निवेश फंसे नहीं, यह भारत की प्राथमिकता है। अब जब अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद वहां के तेल बाजार पर अमेरिका अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेगा तो यह देखना जरूरी है कि भारत के जो ऊर्जा निवेश वेनेजुएला में हैं और 60 करोड़ डालर का लाभांश, जिसका भुगतान भारतीय कंपनियों को अभी तक नहीं हुआ है, वह कैसे होगा।

अब अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद वेनेजुएला में जो प्रतिबंध तेल व्यापार आदि चीजों पर लगाए गए थे उनमें एक संभावित कमी आने के आसार बन सकते हैं जिसका लाभ भारत को मिल सकता है। भारत की स्थिति इस बदले हुए भू-सामरिक समीकरण में बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके लिए अमेरिका से तनावपूर्ण संबंधों से दूर रहना होगा। अमेरिका भारत का किसी भी प्रकार का तनावपूर्ण संबंध इस समय ट्रंप के लिए भारत से सौदेबाजी का बड़ा हथियार है। दुनिया के बड़े तेल भंडारों तक भारत की जो पहुंच है, वह पुनर्बहाल हो सकती है, यदि भारत अमेरिका संबंध सामान्य रहें।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जैसे थिंक टैंक का भी मानना है कि भारत के आर्थिक हितों पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से 2025 के वित्त वर्ष तक भारत के वेनेजुएला से क्रूड आयल के आयात में 81.3 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई है। भारत ने रूस से रिकार्ड पैमाने पर कच्चे तेल की खरीद करते हुए उसके साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 70 अरब डालर तक पहुंचा दिया। भारत इस समय इराक, सऊदी अरब, रूस, यूएई, अमेरिका और नाइजीरिया से कच्चे तेल का आयात कर एक सुरक्षित आयल इंपोर्ट आर्किटेक्चर निर्मित कर चुका है। इसमें यदि अमेरिका को किसी से समस्या है तो वह रूस से है, उस मुद्दे पर भी भारत राष्ट्रीय हितों के अनुरूप तार्किक बदलाव करने से संकोच नहीं कर रहा है।

भारतीय कंपनियों को लाभ की संभावना : वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद भारतीय कंपनियों को अपने एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग गठजोड़ों में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को तेल आपूर्ति एवं वैलुएशन में कुछ संभावित तब्दीली करनी पड़ सकती है। सनफार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा की वेनेजुएला में मजबूत उपस्थिति रही है, जबकि जिंदल स्टील वहां लौह अयस्क कांप्लेक्स को प्रबंधित करती है। इंजीनियर्स इंडिया की भी प्रभावी मौजूदगी वहां है। यदि अमेरिका वेनेजुएला की आयल इंडस्ट्री की रिस्ट्रक्चरिंग करता है तो भारतीय कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इंडियन आयल कारपोरेशन वेनेजुएला के काराबोबो हैवी आयल प्रोजेक्ट में पार्टनर है। यदि वेनेजुएला में तेल उत्पादन, निर्यात, लाजिस्टिक्स में अवरोध आता है तो यह किसी न किसी रूप में भारत के ऊर्जा हितों को तो प्रभावित करेगा ही।

यहां यह विचारणीय है कि भारत और अमेरिका का ऊर्जा व्यापार बढ़ चुका है, दोनों एनर्जी पार्टनर्स हैं। जब अमेरिका ने ईरान के मुद्दे पर भारत को अमेरिकी तेल और एलएनजी खरीदने को कहा था, तो उसके बाद 2017 में भारत ने अमेरिका से एलएनजी खरीदना शुरू किया था। चूंकि अमेरिका तेज गति से भारत के लिए क्रूड आयल और एलएनजी आपूर्तिकर्ता बना है, इससे इस बात की संभावना है कि अमेरिकी संचालित वेनेजुएला आयल कंपनियां भारत के हितों के लिए मददगार साबित हों। वर्ष 2025 में अमेरिका ने एलएनजी निर्यात में पूरी दुनिया में रिकार्ड बना दिया। यह दुनिया का पहला देश बन गया जिसने एक वर्ष में 10 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी का निर्यात दुनिया भर के देशों को किया। अमेरिका वेनेजुएला के हाइड्रोकार्बन भंडारों का महत्व भली-भांति जानता है। अमेरिका ने एक नए प्रकार के एनर्जी वारफेयर को जन्म दिया है जिसमें उसे मध्यपूर्व एवं खाड़ी देशों या अफ्रीकी देशों से दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा रोड़ा उसकी राह में वेनेजुएला रहा है। वेनेजुएला अमेरिका के एनर्जी ट्रेड से जुड़े वैश्विक मंसूबों का गेटवे है। नवंबर 2025 में अमेरिका ने एक माह में ही एक करोड़ मीट्रिक टन एलएनजी का निर्यात कर एक और नया विश्व रिकार्ड बना दिया है।

वेनेजुएला के प्राकृतिक स्रोतों पर अमेरिकी नजर

वेनेजुएला और अमेरिका की लड़ाई लंबी और पुरानी रही है। शीत युद्ध के दौर से ही यह पूंजीवादी उदारवादी बनाम साम्यवादी अर्थव्यवस्था की लड़ाई रही है जो कालांतर में डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों पर केंद्रित हो गई। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला से अवैध प्रवासी अमेरिका में आते हैं और यहां की व्यवस्थाएं खराब करते हैं। ऐसा आरोप ट्रंप मैक्सिको, कनाडा और अन्य पड़ोसी देशों पर भी लगा चुके हैं। उनका कहना है कि मादुरो ने अपनी जेलों में भरे कैदियों को भी अमेरिका जाने के लिए छोड़ दिया। वहीं दूसरी सबसे प्रमुख वजह यह है कि नारकोटिक ड्रग्स फेंटेनिल और कोकीन की सप्लाई वेनेजुएला से अमेरिका में होती है। ऐसा ट्रंप का कहना है और इसलिए ट्रंप ने इसे नार्को टेररिस्ट देश करार दिया और यहां ड्रग्स कार्टल्स के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की और दो सबसे बड़े ड्रग्स कार्टेल को फारेन टेररिस्ट आर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया। फेंटेनिल को ट्रंप 'वेपंस आफ मास डिस्ट्रक्शन' कहते हैं, ठीक वैसा ही जनसंहारक हथियार जिसके आधार पर अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था और वहां तखतापलट कर दिया था।

वेनेजुएला में अबकी तेल और ड्रग्स वह हथियार हैं जिनके लिए ट्रंप ने यह कार्रवाई की है। वेनेजुएला और उसके पड़ोसी देश कोलंबिया और कुछ अन्य दक्षिण अमेरिकी देश चिली, पेरू आदि में जो नार्को टेररिस्ट गैंग्स हैं, उनका प्रभाव पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप समेत उत्तरी अमेरिका पर भी पड़ सकता है, इसलिए भी ट्रंप ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और इस कारण से उन्होंने अमेरिकी युद्धपोतों को कैरीबियाई क्षेत्र में तैनात किया है।

ऐसा अनुमान है कि वेनेजुएला में 200 लाख करोड़ क्यूबिक फीट का प्राकृतिक गैस भंडार है जो पूरे लैटिन अमेरिकी प्राकृतिक गैस भंडार के 60 प्रतिशत से अधिक है। शेवरान, ईएनआइ, रेप्साल, मारेल, प्राम जैसी दिग्गज एनर्जी कंपनियों की निगाह इस पर है। वहीं वेनेजुएला की तेल उत्पादन क्षमता में निकोलस मादुरो की कुप्रबंधनकारी नीतियों के चलते लगातार गिरावट देखी गई। एक समय ऐसा था कि वेनेजुएला ने 90 लाख बैरल तेल प्रतिदिन बेचा जो घटकर 20 लाख और वर्तमान में 10 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, लेकिन मादुरो को इसे सुधारने की फिक्र नहीं रही। मादुरो चाहते तो कोलंबिया, ट्रिनिडाड जैसे कई देशों को कच्चे तेल का निर्यात बढ़ा सकते थे और आयल ट्रेड का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते थे, परंतु उनकी संकीर्ण आर्थिक संरक्षणवादी नीतियों के चलते वेनेजुएला तेल का इतना बड़ा भंडार लेकर भी कुछ खास ताकत नहीं रख पाया। वेनेजुएला के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार होने के भी अनुमान लगाए जा चुके हैं, जिसके चलते अमेरिका की वहां रुचि और बढ़ी। वहीं वेनेजुएला को दुनिया के एलपीजी माडल, विश्व व्यापार की उदार नीतियों, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को अमेरिका की कठपुतली कहने की प्रवृत्ति और दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के राह में रोड़ा बनने के चलते ही दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े क्षेत्रीय व्यापारिक संगठन मर्कोसुर से 2012 में निलंबित कर दिया गया था।

(विवेक ओझा)

Dainik jagaran Page No-9

अमेरिकी हमलों से वेनेजुएला की तेल अर्थव्यवस्था झुलसी

यश कुमार सिंघल

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप सरकार के वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार गिराने के कदम से इस लैटिन अमेरिकी देश की तेल अर्थव्यवस्था पर तेज आंच पड़ी है। अभी इसके और भी प्रभावित होने की संभावना है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद हाल के वर्षों में वेनेजुएला से भारत का तेल आयात पहले ही काफी कम हो गया है।

कच्चे तेल के भंडार में वैश्विक स्तर पर वेनेजुएला की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने वेनेजुएला से 1.65 अरब डॉलर का सामान आयात किया था, जिसमें 93.3 प्रतिशत कच्चा तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद शामिल थे। उसी अवधि में वेनेजुएला को भारत से निर्यात 0.22 अरब डॉलर रहा।

पिछले एक दशक के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद के भारत के आयात में वेनेजुएला की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 में 8.45 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 26 के पहले आठ महीनों में 0.28 प्रतिशत रह गई है। वेलेजुएला अभी अपने तेल भंडारों का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा है। सबसे बड़े तेल भंडार होने के बावजूद 2023 में इस देश का कच्चा तेल निर्यात 4 अरब डॉलर से थोड़ा ही अधिक था। दूसरी ओर 2023 में रूस का कच्चा तेल निर्यात 122 अरब डॉलर का था। वेनेजुएला के पास रूस के मुकाबले एक चौथाई भंडार होने के बावजूद उसका निर्यात काफी कम है।

आंकड़ों के आईने में

तेल ही नहीं, इस लैटिन अमेरिकी देश के पास व्यापक प्राकृतिक गैस भंडार भी हैं और पिछले 4 दशक में उसकी वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ी ही है। वर्ष 1983 में वैश्विक कच्चे तेल भंडार में उसकी हिस्सेदारी 3 प्रतिशत थी जो 2020 में 18 प्रतिशत तक बढ़ी और 2024 में 17 प्रतिशत के स्तर पर रही। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस भंडारों में भी उसकी हिस्सेदारी 1983 में 2 प्रतिशत थी, जो 1995 में सर्वाधिक 5 प्रतिशत तक बढ़कर 2024 में 3 प्रतिशत के स्तर पर दर्ज की गई।

इन देशों से कच्चा तेल मंगाता है भारत

वित्त वर्ष	रूस	इराक	यूएई	स. अरब	अमेरिका	वेनेजुएला
2015	0.25	10.24	9.76	16.77	0.70	8.45
2016	0.13	12.96	9.51	18.30	0.98	6.85
2017	0.61	13.38	10.82	17.92	1.35	6.33
2018	1.40	16.13	8.34	16.40	2.02	5.39
2019	0.99	15.83	9.49	17.40	3.77	5.14
2020	1.70	18.15	12.25	17.73	5.29	4.62
2021	1.77	17.13	14.16	15.73	8.93	0.78
2022	2.25	19.49	12.46	17.07	8.67	0.00
2023	16.37	16.31	12.88	15.84	6.40	0.06
2024	28.23	16.64	9.61	13.69	4.38	0.52
2025	28.75	15.44	13.00	12.39	5.52	0.83
2026*	27.55	14.04	13.28	11.92	8.23	0.28

नोटः *अप्रैल-नवंबर, आंकड़े प्रतिशत में, स्रोत-सीएमआईई, वाणिज्य विभाग

वेनेजुएला पर कार्रवाई से उठे सवाल

कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिका की इस कार्रवाई का स्पष्ट विरोध किया है। मगर प्रचार की रणनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी पीछे नहीं है। समर्थन और विरोध से इतर यह सवाल अनुत्तरित रहेगा कि आखिर मादुरो पर ही यह कार्रवाई क्यों की गई!

पुष्परंजन

वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला और वहां के तात्कालिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के मामले में दुनिया एक बार फिर से बंट गई लगती है। कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिका की इस कार्रवाई का स्पष्ट विरोध किया है। मगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का प्रचार करने की रणनीति भी पीछे नहीं है। समर्थन और विरोध से इतर यह सवाल अनुत्तरित रहेगा कि आखिर मादुरो पर ही यह कार्रवाई क्यों की गई! यदि नशीले पदार्थों की तस्करी ही उनका गुनाह-ए-अजीम है, तो इसको लेकर तो चीन पर भी सवाल उठते रहे हैं। देखा जाए तो वेनेजुएला के विपुल खनिज और तेल पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण, ट्रंप की नीयत को पूरी तरह से उजागर नहीं करता है।

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव का यह सिलसिला पुराना है। वेनेजुएला में वर्ष 1999 में ह्यूगो शावेज के सत्ता संभालने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत हो गई थी। शावेज खुद को समाजवादी और अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोधी बताते थे। उन्होंने अमेरिका को आंख दिखाते हुए क्यूबा और ईरान जैसे कई अमेरिकी विरोधी देशों से दोस्ती बढ़ाई। कहानियां यह भी गढ़ी जा रही हैं कि अमेरिका के हमले का मकसद उस 'स्वघोषित समाजवादी क्रांति' को खत्म करना है, जिसे मादुरो के राजनीतिक गुरु और पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने 1999 में शुरू किया था। बात फिर नशीले पदार्थों की तस्करी पर आती है कि आखिर वह ऐसा कौन सा पदार्थ था, जिसकी वजह से अमेरिका की नींद हराम हो गई थी? यह गांजा, अफीम, चरस-हशीश, या हेरोइन नहीं, बल्कि सबसे घातक नशीला पदार्थ 'फेंटानिल' है। कहा जा रहा है कि इस पदार्थ की तस्करी ने अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली। इसने ट्रंप की आभासी मुद्रा क्रिप्टोकरंसी को तबाह कर दिया। कायदे से बहस फेंटानिल के मुख्य आपूर्तिकर्ता चीन पर और ट्रंप के क्रिप्टो गोरखधंधे पर होनी चाहिए थी।

एक रपट के अनुसार, वर्ष 1999 से अब तक अमेरिका में लगभग दस लाख लोगों की इस नशीले पदार्थ की वजह से मौत हो चुकी है। वर्ष 2020 में नशीले पदार्थों से हुई मौत के कुल मामलों में से 82 फीसद फेंटानिल से जुड़े थे। 2022 में यह संख्या 107,941 पर पहुंच गई। 2025 तक अमेरिका में नशीले पदार्थों से होने वाली मौत की दर दोगुनी से ज्यादा हो गई, इसका मुख्य कारण फेंटानिल की बढ़ती तस्करी को माना गया है। दरअसल, फेंटानिल प्रयोगशाला में बनने वाला एक सिंथेटिक नशीला पदार्थ है, जो मार्फिन से 80-100 गुना और हेरोइन से पचास गुना ज्यादा घातक है। वैसे इसका नियंत्रित इस्तेमाल आमतौर पर अस्पतालों में दर्द कम करने के लिए किया जाता है। इसकी खरीद-फरोख्त के लिए 'डार्कनेट' का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। डार्कनेट बाजार वेब पर एक वाणिज्यिक वेबसाइट है, जिसके जरिए नशीले पदार्थ, हथियार, चोरी किया हुआ डेटा और नकली दस्तावेज का अवैध लेन-देन होता है।

उदाहरण के लिए, 'सिल्क रोड', जो वर्ष 2011 में बना, वह एक डार्कनेट बाजार था। यह बिटकाइन के शुरुआती उपयोगकर्ताओं में से कुछ का ठिकाना था। ज्यादातर डार्कनेट बाजार अमेरिकी कानून प्रवर्तन

एजंसियों से बचने के लिए अपने मंच पर फेंटानिल जैसे नशीले पदार्थों पर साफ तौर पर प्रतिबंध का संकेत देते हैं। बावजूद इसके, कई लोग फेंटानिल पर दिखाई जाने वाली पाबंदी से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। वर्ष 2020 की 'ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन' (डीइए) की रपट

अमेरिका के कानून प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस नशीले पदार्थ से जुड़े लेन-देन में शामिल अधिकांश लोग आभासी मुद्रा क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करते हैं। कई अमेरिकियों को लगता है कि प्रवासी लोग ही उनके देश में फेंटानिल ला रहे हैं। मगर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि फेंटानिल की तस्करी और अवैध बिक्री में प्रवासी लोग केवल पच्चीस फीसद और अमेरिकी नागरिक पचहत्तर फीसद शामिल हैं। अमेरिका का प्रशासन अपने ही घर में इसे रोक पाने में नाकाम रहा। विश्लेषकों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए फेंटानिल की तस्करी के तरीकों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया।

में चीन को फेंटानिल का शीर्ष उत्पादक देश बताया गया था। इस संस्था ने फेंटानिल उत्पादन की एक श्रृंखला का पता लगाया है, जिसमें खतरनाक रसायनों को अवैध रूप से लैटिन अमेरिकी देशों में भेजा जाता है, जहां उनका इस्तेमाल फेंटानिल बनाने के लिए किया जाता है। इसे बाद में बेचने के लिए अमेरिका ले जाया जाता है।

अमेरिका के कानून प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस नशीले पदार्थ से जुड़े लेन-देन में शामिल अधिकांश लोग आभासी मुद्रा क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करते हैं। कई अमेरिकियों को लगता है कि प्रवासी लोग ही उनके देश में फेंटानिल ला रहे हैं। मगर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि फेंटानिल की तस्करी और अवैध बिक्री में प्रवासी लोग केवल पच्चीस फीसद और अमेरिकी नागरिक पचहत्तर फीसद शामिल हैं। अमेरिका का प्रशासन अपने ही घर में इसे रोक पाने में नाकाम रहा। विश्लेषकों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए फेंटानिल की तस्करी के तरीकों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इसका बड़े पैमाने पर विश्लेषण करने के लिए 'चैनालिसिस' ने चीन में सक्रिय फेंटानिल के घटक रसायनों के विक्रेताओं से जुड़े क्रिप्टोकरंसी पते की पहचान की। इनके पास वर्ष 2015 से अब तक 98 मिलियन डालर से ज्यादा की क्रिप्टोकरंसी का पता चला है। चैनालिसिस एक अमेरिकी ब्लाकचेन विश्लेषण फर्म है, जिसका मुख्यालय न्यूयार्क सिटी में है।

सबको इस बात की खलिश है कि भारत ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की कार्रवाई को लेकर संतुलित बयान जारी क्यों किया। भारत ने रविवार को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने पर गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील की। मगर, हम एक घटना का विश्लेषण गहराई से करेंगे, तो बात समझ में आ जाएगी कि भारत के इस बयान के क्या मायने हैं। 18 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर एक सूचना जारी की गई कि 'फेंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी में शामिल होने के कारण भारतीय कंपनी के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के अमेरिकी वीजा रद्द।' दूतावास ने स्पष्ट किया कि ये व्यक्ति अमेरिका की यात्रा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। साथ ही कहा कि दूतावास उन कंपनियों से जुड़े अधिकारियों पर भी कड़ी नजर रख रहा है, जिनके बारे में पता चला है कि उन्होंने फेंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी की है। फेंटानिल के प्रवाह को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यह दिलचस्प है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि नशीले पदार्थों की तस्करी ही मादुरो का मुख्य गुनाह है, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे कि इस अवैध धंधे से उनकी कंपनी की क्रिप्टोकरंसी का कितना नुकसान हुआ है। एक हालिया रपट के अनुसार, वर्ष 2025 के आखिर में क्रिप्टो बाजार में गिरावट के कारण ट्रंप की कंपनी की कुल संपत्ति का मूल्य एक बिलियन डालर से ज्यादा कम हो गया। ब्लूमबर्ग के अनुसार, इस परिवार की संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 7.7 बिलियन डालर से घटकर 6.7 बिलियन डालर रह गया और यह डिजिटल संपत्ति में गिरावट के कारण हुआ है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नशीले पदार्थ फेंटानिल के उत्पादन से जुड़े क्रिप्टोकरंसी-आधारित लेन-देन ने 'ट्रंप मेमेकाइन' को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप अपने इस दर्द को सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वेनेजुएला पर कार्रवाई करके एक तीर के साथ कई निशाने साधे हैं।

Jansatta Page No-6

कुपोषण के खिलाफ बड़े राष्ट्रीय प्रयास में जुटे गृह मंत्री अमित शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्रीय सहकारिता मंत्री आज करेंगे कुपोषण उन्मूलन कान्क्लेव का उद्घाटन
- बच्चों में कुपोषण खत्म करने को सहकारिता और कार्पोरेट क्षेत्र की बढ़ेगी साझेदारी

सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाते हुए कुपोषण के खिलाफ बड़ा राष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कुपोषण उन्मूलन में कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी की अहम भूमिका पर मंगलवार को कान्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीडीबी फाउंडेशन फार न्यूट्रिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सीएसआर कान्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इसका मकसद बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए सहकारिता और कार्पोरेट क्षेत्र की साझेदारी को मजबूत करना है।

कार्यक्रम के दौरान दो महत्वपूर्ण पोषण कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। पहला, सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की सीएसआर योजना के तहत गिफ्टमिल्क कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों के लगभग चार हजार बच्चों को विटामिन ए और डी से भरपूर फ्लेवर्ड दूध दिया जाएगा। यह दूध छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, आइडीबीआइ बैंक की सीएसआर पहल के तहत शिशु संजीवनी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस योजना से महाराष्ट्र के नागपुर जिले

अमित शाह। फाइल

के ग्रामीण इलाकों की आंगनवाड़ियों में पढ़ने वाले करीब तीन हजार बच्चों को पोषण सहायता मिलेगी। शिशु संजीवनी एक खास तरह का पोषक आहार है, जिसे एनडीडीबी ने विकसित किया है। कान्क्लेव में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों, सार्वजनिक और निजी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं और शोध संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यहां पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और यह बताया जाएगा कि मिलकर काम करने से कुपोषण को कैसे खत्म किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह आयोजन बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है।

ग्रोक मामला: एक्स को मिला और 72 घंटे का समय

आशिष आर्यन

सरकार ने इलॉन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को 72 घंटे का अतिरिक्त समय दिया है ताकि वह यह स्पष्ट कर सके कि उसका आर्टिफिशल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक भारत में उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें कैसे बना सका।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक अब प्लेटफॉर्म के पास 7 जनवरी शाम 5 बजे तक का समय है ताकि वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सवालों का जवाब दे सके। इनमें ग्रोक पर किए गए व्यापक तकनीकी, प्रक्रियात्मक और शासन-स्तरीय समीक्षा की रिपोर्ट भी शामिल है।

अधिकारी ने बताया, 'उन्होंने यह कहते हुए अधिक समय मांगा है कि अमेरिका में छुट्टियों और उनकी वैश्विक व कानूनी टीमों की अनुपलब्धता के कारण देरी हुई है। फिलहाल उन्होंने सरकार के आदेशों का पालन करते हुए सभी आपत्तिजनक और अवैध सामग्री हटा दी है।'

इससे पहले इस सप्ताह, आईटी मंत्रालय के साइबर लॉ डिवीजन ने एक्स को पत्र लिखकर कहा था कि वह 'सभी अवैध रूप से उत्पन्न या प्रसारित सामग्री को तुरंत हटाए या उसकी पहुंच समाप्त करे। आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करे और किसी भी तरह से सबूत को नष्ट न करे।'

पत्र में मंत्रालय ने यह भी कहा था कि एक्स को अपनी सेवा शर्तों और एआई-उपयोग प्रतिबंधों को लागू करना चाहिए और 'कड़े निवारक कदम' उठाने चाहिए, जिनमें ग्रोक का उपयोग कर महिलाओं और बच्चों की अश्लील तस्वीरें बनाने वाले खातों को निलंबित करना, समाप्त करना या अन्य कार्रवाई करना शामिल है।

आईटी मंत्रालय के पत्र के एक दिन बाद, मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि 'जो भी ग्रोक का उपयोग कर अवैध सामग्री बनाएगा, उसे वही परिणाम भुगतने होंगे जो अवैध सामग्री अपलोड करने पर भुगतने होते हैं।'

भारत और दुनिया भर में उपयोगकर्ता साधारण निर्देशों से ग्रोक का उपयोग कर महिलाओं और बच्चों की अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें बना सके हैं।

इस मुद्दे ने कई उपयोगकर्ताओं, विशेषकर बड़ी संख्या में महिलाओं में नाराजगी पैदा की है। कई महिलाएं ग्रोक को टैग कर यह निर्देश दे रही हैं कि उनकी तस्वीरों का उपयोग किसी भी आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री बनाने में न किया जाए।

इस मामले के बाद, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी साइट पर मौजूद सामग्री की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

वैष्णव ने कहा, 'आज सोशल मीडिया हमारे समाज में इतना बड़ा प्रभाव डाल रहा है। इन (सोशल मीडिया मध्यवर्तियों) को अपनी साइट पर मौजूद सामग्री की जवाबदेही चाहिए। और ऐसी सामग्री को लेकर हस्तक्षेप होना चाहिए।'

पिछले सप्ताह आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश जारी किया था कि वे अपनी साइट से अश्लील सामग्री हटाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करें। 2025 की अपनी तीसरी एडवाइजरी में मंत्रालय ने उन्हें आईटी नियमों और आईटी अधिनियम का पालन करने की याद दिलाई और कहा कि उन्हें अश्लील और अभद्र सामग्री की निगरानी में अधिक कठोरता बरतनी चाहिए।

मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा था कि मध्यस्थों को उचित परिश्रम संबंधी दायित्वों का पालन करने में अधिक कठोरता दिखानी चाहिए, विशेषकर उस सामग्री की 'पहचान, रिपोर्टिंग और शीघ्र हटाने' में जो 'अशिष्ट, अश्लील, बाल यौन शोषण से संबंधित, बच्चों के लिए हानिकारक या अन्यथा अवैध' हो।

Dainik Jagaran Page -3

Business Standard Page -10

अध्ययन

पुरुषों की भी स्थिति खराब

दो तिहाई बच्चों व महिलाओं में खून की कमी

राकेश शर्मा
नई दिल्ली, 5 जनवरी।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण – पांच के अनुसार देश की जनसंख्या में एनीमिया की समस्या गंभीर है। रपट के अनुसार महिलाओं में (15–49 वर्ष) 57.0 फीसद, किशोरियों (15–19 वर्ष) में 59.1 फीसद, बच्चों (6–59 महीने) में 67.1 फीसद और पुरुषों (15–49 वर्ष) में 25.0 फीसद के आंकड़ों के साथ स्थिति चिंताजनक है।

पोषण सहित दूसरे कारणों से महिलाओं और बच्चों में चुनौती बनी एनीमिया (रक्ताल्पता) की समस्या को नियमित जांच और इलाज से कम किया जा सकता है। यह खुलासा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के सहयोग से राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआइएन) के अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन को तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में किया गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण – पांच के अनुसार देश की जनसंख्या में एनीमिया की समस्या गंभीर है। रपट के अनुसार महिलाओं में (15–49 वर्ष) 57.0 फीसद, किशोरियों (15–19 वर्ष) में 59.1 फीसद, बच्चों (6–59 महीने) में 67.1 फीसद और पुरुषों (15–49 वर्ष) में 25.0 फीसद के आंकड़ों के साथ स्थिति चिंताजनक है। इस समस्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को प्रति वर्ष तीन फीसद कम करना है। शोध के अनुसार इस क्लस्टर यादृच्छिक परीक्षण को तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में किया गया। इसमें कुल 14 क्लस्टर शामिल थे। इन क्लस्टरों को दो समूहों (हस्तक्षेप समूह और नियंत्रण समूह) में बांटा गया। प्रत्येक क्लस्टर में 6 महीने से 50 वर्ष तक की आयु के वे सभी लोग शामिल थे, जिनकी देखरेख एक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता करता है। शोध में शामिल हुए नमूने का कुल आकार 11386 का रहा। इसमें हस्तक्षेप समूह के 6131 और नियंत्रण समूह के 5255 नमूने शामिल रहे।

अध्ययन के दौरान हस्तक्षेप समूह में प्रतिभागियों की विश्व स्वास्थ्य संगठन 2011 मानकों के अनुसार मौके पर ही एनीमिया की जांच की गई। एनीमिया पाए जाने पर उन्हें राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार आयरन-फोलिक एसिड की खुराक दी गई। वहीं, नियंत्रण समूह के प्रतिभागियों को पहले से चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का लाभ दिया गया। अध्ययन के दौरान हस्तक्षेप समूह में 88.6 फीसद लोगों की जांच की गई और 97 फीसद तक उपचार किया गया। इस दौरान दोनों समूहों में शुरुआती विशेषताएं लगभग समान दिखीं। बिना समायोजन के दोनों समूहों के औसत हीमोग्लोबिन स्तर में कोई खास अंतर नहीं दिखा। लेकिन अन्य कारकों को समायोजित करने के बाद, हस्तक्षेप समूह में हीमोग्लोबिन स्तर में वृद्धि दर्ज की गई।

Jansatta Page No-17

जानें-समझें

वेनेजुएला और तेल का खेल

वैश्विक बाजार के लिए मौका या चुनौती

जनसत्ता संवाद

तेल के भंडार पर कब्जे के लिए संघर्ष की खबरें नई नहीं है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने में तेल प्रमुख कारण के रूप में उभरा है। अभी वैश्विक तेल उत्पादन में वेनेजुएला का हिस्सा एक फीसद से भी कम है, लेकिन उस देश के पास विश्व स्तर पर सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसका अनुमान तीन सौ अरब बैरल से अधिक है। मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन काराकस के तेल क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेगा और अमेरिकी कंपनियां वहां अरबों डालर का निवेश करेंगी।

जर्जर स्थिति और ओपेक का मुद्दा

वेनेजुएला का तेल उद्योग वर्षों की उपेक्षा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण जर्जर स्थिति में है। इसलिए उत्पादन के सामान्य होने में कई साल लगेंगे और बड़े निवेश की जरूरत होगी। अमेरिकी तेल कंपनियां तब ही भारी निवेश करेंगी, जब देश में स्थिर सरकार होगी। वेनेजुएला तेल उत्पादक देशों के संगठन 'ओपेक' का सदस्य है, इसलिए उसका उत्पादन पहले से ही ओपेक में शामिल है। इसके अलावा वर्तमान में वैश्विक बाजार में तेल की मात्रा अधिक है। 'यूएस एनर्जी इंफार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन' के अनुसार, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित कच्चे तेल भंडार हैं, जो लगभग 303 अरब बैरल का है। यह वैश्विक भंडार का लगभग 17 फीसद है।

निवेश को लेकर सवाल

भविष्य में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि या निवेश पर अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। केवल शेवरान ही वेनेजुएला में महत्त्वपूर्ण रूप से कार्य कर रही अमेरिकी तेल कंपनी है, जहां यह करीब 2,50,000 बैरल तेल प्रतिदिन का उत्पादन करती है। शेवरान ने 1920 के दशक में वेनेजुएला में निवेश करना शुरू किया था और यह देश की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पेट्रोलियोस डी वेनेजुएला एसए (पीडीवीएसए) के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से अपना काम संचालित करती है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर तेल का उत्पादन और निर्यात करती हैं। वेनेजुएला का राजनीतिक माहौल ऐसा रहा है

(फाइल फोटो)

वेनेजुएला के तेल उत्पादन पर अमेरिकी प्रभुत्व हो जाने से अब दुनिया में तेल का व्यापार प्रभावित होगा। वेनेजुएला के सहयोग से अमेरिका तेल का बड़ा उत्पादक खिलाड़ी बन सकता है जिसके बाद ओपेक अकेले दम पर तेल कीमतों को बढ़ा-घटा नहीं सकेगा। यानी तेल बाजार में ओपेक की दावेदारी काफी हद तक कमजोर हो सकती है।

- नरेंद्र तनेजा, ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ

चीन में तेल कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसका असर अमेरिकी-यूरोपीय देशों पर भी पड़ सकता है। लेकिन इस समय अर्थव्यवस्था का दबाव झेल रहा अमेरिका स्वयं नहीं चाहेगा कि आवश्यक वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति पर असर पड़े। तेल कीमतों में स्थिरता बनाए रखना स्वयं अमेरिका के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। इस कारण वेनेजुएला को वह आगे नहीं छेड़ेगा।

- हीरक दत्ता, ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ

अमेरिका का हस्तक्षेप

अक्तूबर 2023 में अमेरिका ने वेनेजुएला के पेट्रोलियम क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी और छह महीने के लिए बिना किसी सीमा के तेल निर्यात की अनुमति दे दी। इस कारण आरआइएल और कुछ अन्य भारतीय शोधनागारों ने वेनेजुएला से तेल आयात फिर शुरू कर दिया। लेकिन वेनेजुएला में स्वतंत्र और निष्पक्ष राष्ट्रपति चुनाव कराने को लेकर काराकास के साथ हुए समझौते के टूटने के बाद वाशिंगटन ने प्रतिबंधों में छूट की अवधि नहीं बढ़ाई, जिस कारण आयात रुक गया। कुछ महीनों बाद आरआइएल ने अमेरिका से प्रतिबंधों में छूट प्राप्त करने के बाद वेनेजुएला से तेल आयात फिर से शुरू कर दिया। लेकिन 2025 की गर्मियों में ट्रंप प्रशासन द्वारा वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर उच्च शुल्क लगाने की धमकी के बाद कंपनी ने वेनेजुएला से तेल आयात रोक दिया। बीते कई महीनों से भारत में वेनेजुएला से तेल का आयात नहीं हुआ है।

विदेशी कंपनियां भरोसा नहीं कर पातीं कि सरकार उनके साथ किए गए अनुबंधों का सम्मान कर पाएगी या नहीं। वर्ष 2007 में तब के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने देश के अधिकांश तेल उत्पादन को राष्ट्रीयकृत कर दिया था, जिससे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, जैसे एक्सान मोबिल और कोनोको फिलिप्स को अपने कार्य रोकने पड़े और उन्हें देश छोड़ना पड़ा।

भारत की स्थिति

भारत की बात करें तो, निकट भविष्य में इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि भारतीय तेल कंपनियां वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात नहीं करतीं। बाजार में तेल की अधिक आपूर्ति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों पर दबाव भी कम रहने की उम्मीद है, इसलिए भारत के लिए यह कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं करेगा। हालांकि, अगर ट्रंप काराकस को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने के लिए राजी कर लेते हैं, तो भारत को फायदा होगा, क्योंकि इससे वेनेजुएला का तेल उद्योग संभावित रूप से प्रतिबंधों से मुक्त हो सकता है और कारोबार के लिए खुल सकता है।

लाभांश वसूली की उम्मीद

भारत के सरकारी स्वामित्व वाली आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) की विदेशी निवेश शाखा, ओएनजीसी विदेश के लिए वेनेजुएला की दो तेल और गैस परियोजनाओं में अपनी शेयरधारिता से 500 मिलियन डालर से अधिक मूल्य के अटके हुए लाभांश की वसूली का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इससे वेनेजुएला के तेल और गैस क्षेत्र में अधिक भारतीय निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत, विशेष रूप से निजी क्षेत्र की अग्रणी तेल शोधक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल), 2019 में काराकस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले वेनेजुएला से कच्चे तेल का नियमित खरीदार था। प्रतिबंधों के बाद, वेनेजुएला से तेल आयात कुछ ही महीनों में बंद हो गया।

Jansatta Page No-7

योजनाओं के विलय पर जोर

श्रेया नंदी और रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 5 जनवरी

केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित और केंद्र सरकार की योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने और योजनाओं का दोहराव कम करने के लिए मौजूदा योजनाओं में विलय करने के निर्देश दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह कवायद मार्च तक पूरी की जानी है।

अधिकारी ने कहा, 'वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला व्यय विभाग चाहता है कि केंद्र सरकार की और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाया जाए। एक ही तरह की योजनाओं या इच्छित परिणाम न दे रही योजनाओं को जरूरत के मुताबिक विलय या बंद किया जाना चाहिए। इस समय योजनाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। युक्तिसंगत बनाने से योजनाओं की बेहतर निगरानी में मदद मिलेगी।'

सरकारी विभाग और मंत्रालय इस सिलसिले में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे और इस पर अंतिम निर्णय व्यय विभाग द्वारा लिया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, 'कई योजनाओं का अगले वित्त वर्ष के लिए मूल्यांकन किया जाना है। यह कवायद उससे पहले पूरी की जानी है।' केंद्रीय बजट 2026-27 एक फरवरी को पेश किए जाने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती हैं। बहरहाल इस पर आने वाले खर्च का वहन एक निश्चित अनुपात में राज्य व केंद्र दोनों सरकारें करती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन इस तरह की योजनाओं में शामिल हैं।

वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ही धन मुहैया कराती है और वही उसका कार्यान्वयन भी करती है। ऐसी योजनाओं में खाद्य सब्सिडी, उर्वरक सब्सिडी, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के आवंटन और विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे फसल बीमा योजना, ड्यूटी ड्रॉबैक योजना, जन औषधि योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) शामिल हैं।

व्यय विभाग के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 54 योजनाएं हैं, वहीं केंद्र सरकार की 260 योजनाएं हैं, जिनकी अनुमोदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक है और इनका मूल्यांकन किया जाना है। योजनाओं को युक्तिसंगत बनाए जाने और उनके समेकन की कवायद 5 साल पहले वित्त सचिव टीवी सोमनाथन द्वारा शुरू की गई थी, जो इस समय कैबिनेट सचिव हैं। इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को केंद्र सरकार की और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिनकी अवधि समाप्त हो रही है या 31 मार्च, 2026 के बाद भी उन्हें जारी रखा जाना है।

सरकारी विभागों से मांगे गए ब्योरे में तीसरे पक्ष का मूल्यांकन, प्रस्तावित योजना में अगले 5 साल तक हर साल के मुताबिक आवंटन और इसमें किए गए बदलाव का ब्योरा शामिल है।

बजट के पहले सरकार की कवायद

- केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 54 योजनाएं हैं, वहीं केंद्र सरकार की 260 योजनाएं हैं
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र व राज्य दोनों धन देते हैं और राज्य सरकारें उन्हें लागू करती हैं
- केंद्र की योजनाओं के लिए केंद्र धन मुहैया कराता है, वही उसका क्रियान्वयन करता है
- व्यय विभाग ने दोहराव वाली योजनाओं के विलय या वांछित परिणाम न दे रही योजनाओं को बंद करने के निर्देश दिए हैं

Business Standard Page -4

बिनय सिन्हा

रिजर्व बैंक और सरकार के रिश्ते सुलझाने का वक्त

केंद्रीय बैंक और देश की सरकार के बीच रिश्ते को अक्सर पारंपरिक विवाह की तरह देखा जाता है। लेकिन यह रिश्ता वित्तीय क्षेत्र को पीछे की ओर धकेल रहा है। बता रहे हैं अजय छिब्बर

हम साल 2026 में प्रवेश कर गए हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर देश की अर्थव्यवस्था को 'गोल्डीलॉक्स' बता रहे हैं जहां वृद्धि मजबूत है और मुद्रास्फीति कम। श्रम सुधारों के बाद अगला लक्ष्य यह होना चाहिए कि वित्तीय बाजारों की गहराई बढ़ाकर पूंजी की लागत को कम किया जाए। यह शायद वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच के रिश्तों की उलझन को सुलझाने का माकूल वक्त है। दोनों के बीच हितों के टकराव के हालात बने हुए हैं और अगर भारत को वित्तीय तंत्र का आधुनिकीकरण करना है तो इसे दूर करना होगा।

इस रिश्ते को अक्सर पारंपरिक विवाह की तरह देखा जाता है जहां वित्त मंत्रालय पति और रिजर्व बैंक पत्नी की भूमिका में है। जबकि सरकार सास की भूमिका में रहती है। विवाद अक्सर घर में ही सुलझ जाते हैं और सार्वजनिक नहीं होते। तलाक का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर विवाद पैदा होता है तो सरकार यानी सास अपने बेटे यानी वित्त मंत्रालय का पक्ष लेती है। लेकिन कई बार विवाद बढ़ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना तब हुई थी जब 2018 के आरंभ में सरकारी क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इसमें नीरव मोदी और मेहुल चौकसी शामिल थे, जो अब भी फरार हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिजर्व बैंक पर आरोप लगाया था कि उसने सही नियामकीय निगरानी नहीं बरती। वहीं आरबीआई गवर्नर ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में जवाबी हमला करते हुए कहा कि सरकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के नियामकीय अधिकार बहुत सीमित हैं। सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच करीब 12 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाले। इससे पता चलता है कि उनमें नियमन और निगरानी संबंधी गंभीर खामियां हैं। पीएनबी में एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। निजी वाणिज्यिक बैंकों में भी दिक्कत हुई लेकिन ऐसी नहीं जैसी सरकारी बैंकों में नजर आईं।

सरकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की निगरानी कमजोर है क्योंकि एक ओर जहां वह निजी बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों की नियुक्ति की मंजूरी देता है ताकि वे सही ढंग से काम कर सकें, वहीं सरकारी बैंकों के मामले में उसके पास यह अधिकार नहीं है। सरकारी बैंकों के मुख्य कार्याधिकारी जानते हैं कि उन्हें वित्त मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना होगा न कि अपने आधिकारिक नियामक के।

इस नियामकीय संबंध को और भी जटिल बनाने वाली बात यह है कि रिजर्व बैंक के अधिकारी हर सरकारी बैंक के बोर्ड में बैठते हैं और इस प्रकार वे बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, जबकि वे स्वयं नियामक भी हैं। पीएसबी में बार-बार फंसे हुए कर्ज के मामले सामने आते हैं। इससे संकेत मिलता है कि यह व्यवस्था उनके पर्यवेक्षण कार्यों में मददगार नहीं है। कुछ आरबीआई गवर्नरों ने महसूस किया है कि यह व्यवस्था स्वस्थ नहीं है, जबकि अन्य इससे सहज रहे। 1998 की नरसिंहम समिति-2 ने एक समाधान सुझाया था, जिसमें अनुशंसा की गई थी कि रिजर्व बैंक पीएसबी बोर्डों में न बैठे और पीएसबी बोर्डों को पेशेवर बनाने को बढ़ावा दिया जाए लेकिन अब तक इसे वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया है। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय तथा सरकार के रिश्तों में दूसरी बड़ी समस्या यह है कि रिजर्व बैंक सरकार का ऋण प्रबंधक भी है। यह बात मौद्रिक नीति से संबंधित उसकी भूमिका से हितों का भारी टकराव उत्पन्न करती है। ऋण प्रबंधक के रूप में रिजर्व बैंक ब्याज दरों को कम रखना चाहेगा ताकि सरकार न्यूनतम संभव दर पर ऋण हासिल कर सके। यह बैंकों को सरकारी बॉन्ड रखने के लिए विवश करता है। यह नकदी संबंधी उनकी आवश्यकताओं के साथ हस्तक्षेप करता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी की आवश्यकताएं असामान्य रूप से अधिक हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें अत्यधिक घाटे में चलती हैं। उधारी की लागत को कम रखने के लिए, सरकार एक सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लागू करती है, जिसके तहत बैंकों को सरकारी बॉन्ड रखने होते हैं जिन्हें नकदी का ही एक रूप माना जाता है।

भारत का एसएलआर 1980 के दशक के 40 फीसदी से घटकर 18 फीसदी पर आ गया है। लेकिन भारत, बांग्लादेश (13 फीसदी) और पाकिस्तान (15 फीसदी) के साथ, अब भी उन कुछ देशों में शामिल है जो इस पुराने साधन का उपयोग करते हैं। यह वाणिज्यिक बॉन्ड बाजार के विकास को नुकसान पहुंचाता है और निजी ऋण वृद्धि को बाधित करता है। भारत का निजी ऋण-जीडीपी अनुपात अब भी बेहद कम है, जीडीपी के लगभग 50 फीसदी के बराबर। यह बांग्लादेश और पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों से बहुत पीछे है, जहां यह जीडीपी के 100 फीसदी से भी अधिक है।

इससे संबंधित एक समस्या यह है कि रिजर्व बैंक सरकारी बॉन्ड बाजार का नियमन भी करता है और उसमें एक कारोबारी की तरह शामिल भी होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी वाणिज्यिक बॉन्ड बाजार का नियमन करता है। दो बार यानी पहले 2007 में और फिर 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम और जेटली ने, जो अलग-अलग दलों से थे, यह घोषणा की कि सार्वजनिक ऋण प्रबंधन का काम आरबीआई से अलग राष्ट्रीय ट्रेजरी डेट कार्यालय को सौंपा जाएगा। लेकिन दोनों बार इस घोषणा को बिना वजह बताए वापस ले लिया गया। वित्त मंत्रालय में ऋण प्रबंधन इकाई 2015 में गठित की गई ताकि ऋण संबंधी नीतियां बन सकें और जोखिम का विश्लेषण हो। साल में दो बार रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ऋण प्रबंधन को लेकर मशविरा करते हैं। परंतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने इसकी खराब रेटिंग की है। चाहे जो भी हो, हितों के टकराव का प्रश्न भी बरकरार है।

सुधार इसलिए भी मुश्किल रहे क्योंकि राज्यों और केंद्र का संयुक्त घाटा बहुत अधिक है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने इस राजकोषीय दबदबे की लागत का दस्तावेजीकरण किया था। उन्होंने दिखाया कि यह किस तरह ऋण और बॉन्ड बाजार चैनलों के माध्यम से निजी क्षेत्र को बाहर कर देता है। यही नहीं, यह मौद्रिक प्रसारण को नुकसान पहुंचाता है तथा वित्तीय प्रणाली की गहराई को बाधित करता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। मुद्रास्फीति घटकर लचीली व्यवस्था की निचली सीमा से भी नीचे आ गई है और ट्रंप के शुल्क थोपने के बाद भी अर्थव्यवस्था अच्छी तरह बढ़ रही है। आरबीआई ने अभी ब्याज दरें घटाई हैं, इसलिए वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अधिक राजकोषीय खर्च अभी जरूरी नहीं है। हालांकि कारोबारी लॉबी और राजनेताओं की ऐसी ही मांग है।

आगामी बजट एक अवसर है जिसका इस्तेमाल गंभीर राजकोषीय मजबूती के लिए तथा रिजर्व बैंक और सरकार के बीच के खराब रिश्तों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। यह जरूरी है क्योंकि ऐसे हालात देश के वित्तीय क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। इसकी शुरुआत एसएलआर को हटाकर की जा सकती है। इससे वित्त मंत्रालय पर अतिरिक्त दबाव बनेगा कि वह राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाए। एक सौहार्दपूर्ण तलाक हमेशा एक खराब शादी से बेहतर होता है।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी में विशिष्ट अतिथि विद्वान हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

Business Standard Page -5

सहकारिता को बजट में मिल सकता है बढ़ावा

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 5 जनवरी

इस क्षेत्र के माध्यम से 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने और आर्थिक योगदान को 3 गुना करने के तरीके को स्पष्ट करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किए जाने की संभावना

केंद्रीय बजट 2026-27 में सहकारिता क्षेत्र पर जोर दिए जाने की संभावना है। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की हिस्सेदारी मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए बजट में एक खाका पेश किया जा सकता है। इसका मकसद राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी) 2025 के लक्ष्यों के अनुरूप 50 करोड़ लोगों को इसके दायरे में लाना है।

सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कुछ महीने पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा पेश की गई राष्ट्रीय सहकारिता नीति में सहकारिता से जुड़े लोगों की संख्या मौजूदा 30 करोड़ से 66 प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्यबल गठित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। साथ ही सहकारिता में कामकाज को स्वायत्त बनाने और सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस नीति में सहकारी समितियों की संख्या में मौजूदा लगभग 8,30,000 के स्तर से 30 प्रतिशत बढ़ाने का भी आह्वान किया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आगामी केंद्रीय बजट से उपरोक्त उल्लिखित नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके पर एक स्पष्ट खाका पेश किए जाने की उम्मीद है।'

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सहकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी का कोई प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है, लेकिन सेक्टर के आंकड़े इसके आर्थिक महत्त्व को रेखांकित करते हैं। 2016-17 आंकड़ों के मुताबिक कुल कृषि ऋण में सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत, उर्वरक उत्पादन में 25 प्रतिशत और चीनी उत्पादन में 31 प्रतिशत थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में बनी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई नति के कार्यान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर शाह की अध्यक्षता वाली 2 स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से की जा रही है। अन्य सिफारिशों के अलावा राष्ट्रीय सहकारी नीति में सहकारी बैंकों के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए एक नए नैशनल एपेक्स कोआपरेटिव बैंक बनाने की वकालत की गई है।

किफायती ऋण की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ((डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों के मौजूदा तीन-स्तरीय ऋण संरचना को बनाए रखा गया है।

Business Standard Page -4